प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है...
स्वामी महावीर

वर्ष-02, अंक -47 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 27 अगस्त 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुशांत सिंह राजपूत केस

नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग कनेक्शन में रिया समेत 5 पर केस दर्ज किया

सीबीआई ने सुशांत के कुक और इमारत के वॉचमैन से पूछताछ की

मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, जया साहा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना के आदेश पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली की यूनिट, मुंबई एनसीबी के साथ मिलकर इस मामले की जांच करेगी।

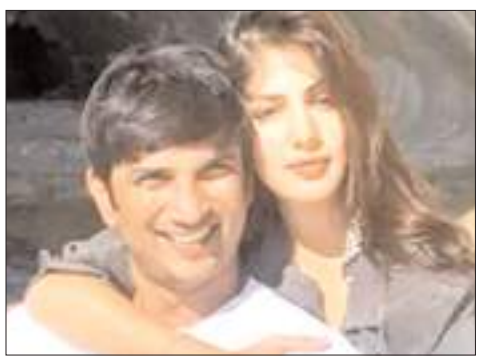

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के मोबाइल से डिलीट हुए कुछ चैट्स एक्सेस किए थे और इन्हें एनसीबी को सौंपा गया था। इन चैट में रिया की ड्रग्स के लिए कई लोगों से बातचीत सामने आई है। उधर, सीबीआई भी लगातार मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने आज सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और वॉचमैन से पूछताछ की। इसके अलावा दो पुलिसकर्मियों से भी सवाल-जवाब किए गए।

मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल को नोटिस भेजा

महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। इसमें रिया चक्रवर्ती को मॉर्चुरी में जाने की इजाजत देने पर सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने अस्पताल मैनेजमेंट और पुलिस से पूछा है कि किन नियमों के तहत रिया को परमिशन दी गई थी?

नारकोटिक्स ब्यूरो रिया से पूछताछ करेगी

एनसीबी अगले एक-दो दिन में एनसीबी की टीम रिया से पूछताछ कर सकती है। ईडी ने रिया के फोन से डिलीट किए गए चैट का रिकॉर्ड रिकवर किया था। ईडी ने रिया का फोन 10 अगस्त को जब्त किया था। इसमें रिया की तरफ से ड्रग्स की बात किए जाने का जिक्र है। उधर, रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने ड्रग्स की थ्योरी को खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में रिया किसी भी जांच से गुजरने को तैयार हैं। उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली।

सुशांत के पिता के वकील बोले- सीबीआई बड़ा खुलासा कर सकती है

सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है ड्रग्स मामले में न्यूज चैनल्स ने मंगलवार को जो बातें बताई, वे सही हैं तो यह बहुत गंभीर मामला है। अगर वाकई सुशांत को प्रतिबंधित दवाएं दी जा रही थीं, तो यह आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ ही मर्डर या फिर इन दोनों के एंगल से जांच का मामला हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि सीबीआई कुछ बड़ा खुलासा करेगी।ठ

सीबीआई आज रिया को समन भेज सकती है

सीबीआई ने दो पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। जांच एजेंसी ने सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टर्स से भी बात की है। माना जा रहा है पोस्टमार्टम टीम से जुड़े 3 और डॉक्टर्स से पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई आज रिया और उनके परिवार को भी समन भेज सकती है।

संदीप सिंह को ईडी समन भेजेगा

सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह से भी जल्द पूछताछ होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संदीप को समन भेजेगा। सुशांत की मौत के बाद संदीप अचानक पिक्चर में आए थे और घर से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक देखे गए थे।

राहुल गांधी की सरकार को नसीहत देकर बताया कैसे पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि, ध्यान भटकाने से नहीं, बल्कि खर्च बढ़ाने और गरीबों के हाथों में पैसे देने से अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।

गांधी ने ट्वीट कर कहा 'जिस बारे में मैं, महीनों से आगाह कर रहा था उसकी पुष्टि आरबीआई ने की है। सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीब को पैसा दीजिए, उद्योगपतियों के कर में कटौती नहीं। खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाइए।' कांग्रेस नेता ने कहा कि, मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और न ही आर्थिक त्रासदी गायब होगी। आरबीआई ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि, अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा, भारत को सतत वृद्धि की राह पर लौटने के लिए तेजी से और व्यापक सुधारों की जरूरत है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, 'साल के दौरान अबतक सकल मांग के आकलन से पता चलता है कि, खपत पर असर काफी गंभीर है और इसके पटरी पर तथा कोविड-19 के पूर्व स्तर पर आने में लंबा समय लगेगा।'

भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से जीएसटी पर कुल कर देनदारी पर लगेगा ब्याज

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल कर देनदारी पर ब्याज लगेगा। वर्ष की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46 हजार करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्तमंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि, 1 जुलाई 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि, 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि, यह अधिसूचना जीएसटी परिषद के फैसलों से अलग लग रही है, जिसमें करदाताओं को यह भरोसा दिया गया था कि, उक्त लाभ 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे।

मुखर्जी अब भी है कोमा में

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहरे कोमा में हैं और जीवनरक्षण प्रणाली पर ही हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी। मुखर्जी (84) का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि, वह अब भी वेंटिलेटर पर हैं। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। इसके बाद उनके फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया और इसका भी इलाज किया जा रहा है। अस्पताल से बताया जा रहा कि, मुखर्जी को जब भर्ती कराया गया था, तब ही कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। अस्पताल ने एक बयान में कहा, श्री प्रणब मुखर्जी का फेफड़ों में संक्रमण का इलाज जारी है। कल से उनके गुर्दे में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। वह अब भी गहरे कोमा में है और जीवनरक्षक प्रणाली पर ही हैं।

कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत से फिर आई अच्छी खबर, मानव पर दूसरे चरण का परीक्षण शुरू

पुणे एजेन्सी। ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का मानव पर दूसरे चरण का क्लीनिकल परीक्षण बुधवार को एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू हो गया। इस टीके का विनिर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, दो स्वयंसेवियों को भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में टीके की खुराक दी गई। ये दोनों पुरूष हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षण दोपहर एक बजे शुरू हुआ। भारती विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के मेडिकल निर्देशक डॉ संजय ललवानी ने कहा, ''अस्पताल के चिकित्सकों ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति की कोविड-19 जांच रिपोर्ट और एंटीबॉडी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे 'कोवीशील्ड' टीके की पहली खुराक दी, वही 48 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति को भी इस टीके की खुराक दी गई।

सड़क पर छेड़खानी के दौरान हादसे में छात्रा की मौत, अमेरिका में पढ़ाई करती थी पीड़िता

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में अपराधियों का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। दादरी की रहने वाली एक लड़की की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह लड़की अमेरिका में पढ़ाई करती थी। सिटी एसपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि, इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

जानकारी के मुताबिक वह अपने चाचा के साथ बाइक पर बैठकर अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। रास्ते में ही बुलेट सवार मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। इसी क्रम में मनचलों से बचने के क्रम में उसके चाचा की बाइक असंतुलित हो गई और लड़की बाइक से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। वह एक मेधावी छात्रा थी, इंटर में टॉप करने के बाद स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने चली गई थी। बुलेट पर सवार मनचले बार-बार बाइक पर सवार होकर जा रही छात्रा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वे उनकी बाइक को बार-बार ओवरटेक कर रहे थे जिसके कारण उनकी बाइक असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो गई।

रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में कहा-केस आगे नहीं ले जाना चाहती, झूठी शिकायत पर कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

मुंबई एजेंसी। मुंबई हाईकोर्ट ने एक महिला पर अपने पुरुष मित्र के खिलाफदुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए मामले का निपटारा किया गया। महिला ने अदालत में याचिका दाखिल करके कहा था कि, वह इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहती। न्यायमूर्ति आरडी धानुका एवं न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने महिला को महाराष्ट्र पुलिस कल्याण कोष में चार सप्ताह के भीतर 25 हजार रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो पुरुष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने का उसका आदेश वापस हो जाएगा। महिला ने 16 मार्च को अपने पुरुष मित्र के खिलाफपालघर जिले के नालासोपारा पुलिस

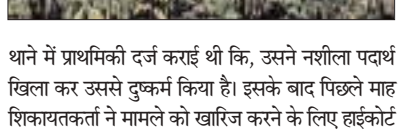

थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि, उसने नशीला पदार्थ खिला कर उससे दुष्कर्म किया है। इसके बाद पिछले माह शिकायतकर्ता ने मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि, उसने परिवार के दबाव में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि, उसके पुरुष के साथ संबंध हैं, लेकिन जब उसके परिवार को इसका पता चला तो उसने कहानी गढ़ दी कि, पुरुष ने उससे दुष्कर्म किया है। याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा कामत पाई ने कहा कि, पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पर आरोप-पत्र दाखिल करेगी। अदालत ने कहा कि, अब याचिकाकर्ता शिकायत को आगे नहीं ले जाना चाहती है, तो हम प्राथमिकी को रद्द करते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि याचिकाकर्ता महाराष्ट्र पुलिस कल्याण कोष में चार सप्ताह के भीतर 25 हजार रुपए जमा कराए।

गधे के मुंह में घास के साथ आ गया सर्प

प्रतापगढ एजेंसी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गधे और सर्प के बीच हुए संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गधे के मुंह में घास के साथ सर्प आ गया, जिसके बाद उसने उसे मुंह से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया और अंत में दोनों की मौत हो गई। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है। जहां एक गधा घास चर रहा था, तभी अचानक से उसके मुंह में घास के साथ सर्प आ गया और वह उसके मुंह में फंस गया, जिसके बाद उसने उसे मुंह से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन गधा सफल नहीं हो पाया और अंत में दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, दोनों के बीच एक-दूसरे से बचने और छूटने का काफी देर तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन ना तो गधा सर्प को अपने मुंह से निकाल पाया और ना सर्प गधे को काटने से खुद को रोक पाया। थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो गई। यह पूरी घटना कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि घटना प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट इलाके की बताई जा रही है। यहां माही नदी के तट पर गधा सुबह घास चरने में व्यस्त था। वह घास के लिए इधर-उधर मुंह मार रहा था। इसी दौरान उसके मुंह में वहां घास में बैठा सर्प भी मुँह में आ गया। सर्प के बीच का हिस्सा गधे के मुंह में आ गया था, जिससे वह गधे के जबड़े में फंस गया। गधे ने सर्प को मुह में से निकालने के लिए कई बार अपने सिर को झटके दिए, लेकिन वह उसके जबड़े से नहीं निकल पाया।

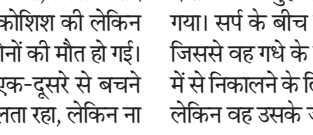

कोरोना संक्रमण के साथ प्रशासन आखिर किस तरह से कर रहा है अपनी जवाबदेही की पूर्ति!

माही की गूंज च.शे.आजाद नगर, अभिषेक गुप्ता

कोरोना संक्रमण की इस महामारी में कई बातें हमें सीखने व देखने को मिली है, तो कई बातें ऐसी भी है जो शायद इतिहास बनकर भी रह जाएगी और इस काल में हर कोई जितना परेशान हुआ है या हो रहा है शायद ही कभी ऐसा फिर ना हो। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के साथ अभी तक अनलॉक के बाद एक के बाद एक कई दिशा-निर्देश जारी हुए और उसे अमल करवाने के लिए प्रशासन ने अपनी सजगता भी दिखाई।

बात करें आजाद नगर की ही तो यहां पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश को पालन करवाने के नाम पर प्रशासन ने व्यापारी से लेकर आम आदमी तक को कई यातनाएं भी दी। व्यापारियों द्वारा अगर आदेशानुसार 10 मिनट पहले या बाद में भी दुकानें खोली या बंद करी गई तो उस पर कानूनी डंडे के साथ एहतियात बरतने का हवाला देकर दो-दो हजार रूपए तक के चालान बनाए गए। इसी क्रम में किसी के मुंह पर नाक के नीचे भी मास्क रहा तो उसका चालान बनाया या फिर उस उस व्यक्ति के साथ प्रशासनिक नुमाइंदों ने ऐसे-ऐसे रोब झाड़े कि उसे देखने व सुनने में भी आश्चर्य होता है, तो ऐसे में तू-तू मैं-मैं की स्थिति भी आमजन के साथ हो गई। वही कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कन्टेनमेंट एरिये को बनाए जाने व जांच रिपोर्ट को लेकर प्रशासन के मनमापिक रवैये पर भिन्न-भिन्न चर्चाएं लोगों में होती रही और यह सारे कार्य प्रशासन के नुमाइंदों ने एहतियात का हवाला दे-देकर किया।

प्रशासन के नुमाईदे जो करे व जो कहे वही सही बाकी सब गलत

वहीं दूसरी ओर माही की गूंज के पास वर्तमान का जीप में भरी ओवरलोड सवारी

का यह फोटो आया, ऐसे फोटो को देखकर कोरोना के पूर्व तो कोई आश्चर्य नहीं होता था और दुर्घटना के संदेह को लेकर समाचार अवश्य प्रकाशित होते रहे है, लेकिन इस कोरोना काल में सारे शासन व प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे फोटो सामने आने पर वर्तमान स्थिति में आश्चर्य जरूर होता है कि, जो प्रशासन के नुमाइंदे अपना रौब झाड़-झाड़कर एहतियात के नाम से लोगों को कई तरह की यातनाएं भी दी। वहीं दूसरी ओर उसी प्रशासन के सामने स्थानीय आजाद नगर के थाने के सामने से होकर और लोडिंग ऊपर-नीचे सवारी से भरी हुई जीप सरेआम आ-जा रही है, तो इसे कोई देखने वाला नहीं है क्या? प्रशासन की इस कार्यप्रणाली के साथ इस भयावह कोरोना संक्रमण की बीमारी से प्रशासन निजात दिलाने की बात या कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की इस दुर्लभ कार्यप्रणाली को देख कहा जा रहा है कि, कोरोना संक्रमण के साथ प्रशासन आखिर किस तरह से कर रहा है अपनी जवाबदेही की पूर्ति ? बतादे कि, कुछ दिन पूर्व भी गूंज ने खुलासा किया था कि, किस तरह से बडवानी से कोरोना काल में प्रतिबंधित के बाद भी बिना परमीट व अवैध रूप से दौ पैसेन्जर बस आजाद नगर होकर जा रही थी की जिसे सेजावडा चौकी पर पकड कर खडी करवाई गई थी बाद में राजनितिक आकाओ के प्रभाव में आकर जवाबदारो ने 7-7 हजार की चालानी कार्रवाई का हवाला देकर अपने कार्य की इतिश्री की थी, इसलिए क्षेत्र में यह भी कहा जा रहा है कि, प्रशासन के नुमाईदे जो कहे और जो करे वही सही बाकी सब गलत।

उमा भारती का तंज

गांधी-नेहरू परिवार का अस्तित्व संकट में, कांग्रेस अब समाप्त हो गई

भोपाल। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़ी बहस के बीच भाजपा नेताओं का पार्टी पर हमला जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। वहीं, मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसा स्कूल है, जहां हेडमास्टर का बच्चा ही टॉप करता है। उमा भारती ने कहा, गांधी-नेहरू परिवार का अस्तित्व संकट में है, उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो गया है। कांग्रेस अब समाप्त हो गई है, इसलिए कौन किस स्थिति में है, यह अब शायद ही मायने रखता है। कांग्रेस को गांधी के पास लौटना चाहिए, असली 'स्वदेशी' गांधी के पास जो बिना किसी विदेशी तत्व के। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती का कहना है कि अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा- हम सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, इस पूरे मामले में राजनीति ना करें, क्षेत्रवाद की राजनीति ना करें।

दिग्विजय सिंह ने कहा- अब राहुलजी को जिद छोड़ देना चाहिए। अगर सोनिया गांधी पद छोड़ना चाहती हैं, तो राहुल को अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल तो पहले ही अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। उनको पता है कि यह उनके बस की बात नहीं है।

प्रदेश में वनाधिकार दावों का निराकरण 15 सितम्बर के पूर्व हो

भोपाल। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पूर्व में निरस्त वनाधिकार दावों का निराकरण अनिवार्य रूप से 15 सितम्बर के पूर्व किया जाए। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी लम्बे समय से वन भूमि में काबिज हैं उनके वनभूमि के पट्टे नियम के अनुसार मान्य किए जाए। आदिम जाति कल्याण मंत्री मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से इंदौर और उज्जैन संभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में छात्रवृत्ति, आवासीय सहायता और छात्रावासों में प्रवेश की स्थिति की समीक्षा भी की गई। आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम में पूर्व में निरस्त दावों की पुन: समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इस काम को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए निर्देश

शहरों में कचरे के निपटान के लिए एक हफ्ते के अंदर बनाएं ठोस नीति

भोपाल (विशेष प्रतिनिधि)

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने शहरों के कचरे के निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्यवाही की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सात क्लस्टरों में शामिल 109 नगरीय निकायों के अतिरिक्त अन्य निकायों में कचरे के प्र-संस्करण के लिए एक सप्ताह में ठोस नीति बनाएं। आवश्यकतानुसार नगरीय निकायों में छोटे-छोटे ठोस अपशिष्ट प्र-संस्करण प्लांट लगाने पर विचार किया जा सकता है। सिंह ने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि शहरों में कचरे के ढेर नहीं दिखें। श्री सिंह ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिन क्लस्टरों का टेंडर हो चुका है, वहाँ पर जल्द कार्यवाही करें। सात क्लस्टरों में से मात्र सागर और कटनी में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में प्लांट शुरू करने के लिए जरूरी कार्यवाही 7 दिन में करें। सिंह ने कहा कि यदि नगर निगम स्तर पर लापरवाही हो रही है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नीमच और खण्डवा क्लस्टर के संबंध में भी एक सप्ताह में निर्णय लें। रीवा का प्लांट डेढ़ माह में चालू करें।

राज्य के वरिष्ठ पुलिस अफसर की पहले लोकायुक्त में हुई थी शिकायत

भोपाल (विशेष प्रतिनिधि)

मध्य प्रदेश की राजधानी में आयकर विभाग की टीमों के फेथ बिल्डर के दफ्तर और उससे जुड़े लोगों के कई स्थानों पर दी गई दबिश के बाद पर्दे के पीछे की बड़ी कहानी सामने आने लगी है। जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बड़े रसूखदार नौकरशाहों पर भी आंच आने के आसार बनने लगे हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों आयकर विभाग की टीमों ने फेथ बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर के ऑफिस सहित उसके और उससे जुड़े पियूष गुप्ता के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। कहा तो यह जा रहा है कि आयकर विभाग को जो दस्तावेज मिले हैं, उसके मुताबिक सौ से ज्यादा संपत्तियों का ब्यौरा उसके हाथ लगा है।

आयकर के छापों के बाद जो बातें सामने आई है वह चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ पहले लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। इसमें संपत्ति और निवेश का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया गया था। इतना ही नहीं यह मामला भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय तक गया। उसके बाद छानबीन हुई और यह पाया गया कि भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सौ से अधिक संपत्तियों में निवेश किया गया है।

बेनामी प्रापर्टी के दस्तावेजों की हो रही पड़ताल

बड़े रसूखदार-नौकरशाहों तक पहुंची आयकर छापों की आंच

दस्तावेजों की स्क्रूटनी के साथ जारी होंगे नोटिस

20 से ज्यादा आवासीय भूखंड

सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग को भोपाल में रातीबढ़ में लगभग दो सौ एकड़ क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अलावा 20 से ज्यादा आवासीय भूखंड, सात फ्लैट, छह मकान, होटल, रिसोर्ट एवं आवासीय परियोजनाएं, शॉपिंग मॉल, दुकानें आदि में निवेश की पुष्टि हुई है। उसके बाद ही छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

राजसात हो सकती है कई संपत्ति

आयकर विभाग के सूत्रों का दावा है कि जिस बेनामी संपत्ति का पता चला है उसमें से कई संपत्तियों को राजसात भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट में वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से बेनामी संपत्ति को राजसात करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी की तैनाती भी की गई है। संपत्ति राजसात की प्रक्रिया को ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर का अधिकारी आयकर के प्रतिवेदन के पंद्रह दिन बाद अंजाम दे सकता है।

होटल खरीदी का मामला भी विवादों में

आयकर के छापों में जिन संपत्तियों का खुलासा हुआ है उनमें भोपाल में एक होटल की खरीदी का मामला भी विवादों में है। बताया जा रहा है कि यह होटल बैंक से कर्ज लेकर एक व्यक्ति ने बनाया, वह कर्ज नहीं चुका पाया तो उसको बैंक ने जब्त कर नीलामी की प्रक्रिया अपनाई। जब उसका मूल्यांकन कराया गया तो होटल की स्थिति को ही बदल दिया गया, ताकि संपत्ति की कीमत को कम आंका जा सके, जिससे होटल की कीमत में बड़ा बदलाव आ गया, परिणामस्वरूप होटल कम कीमत पर बिका, साथ ही राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी हुई। इस मामले की जांच लंबित है।

कई राज्यों से जुड़े तार

सूत्रों की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय को जो शिकायत की गई है उसमें भोपाल के अलावा इंदौर, लखनऊ, मुंबई, मसूरी, गोवा, दिल्ली में भी बेनामी संपत्तियों और बेनामी कंपनियों का ब्यौरा भी दिया गया है। इस पर भी कार्रवाई आगामी समय में संभावित है। इस शिकायत में एक गठजोड़ की तरफ भी इशारा किया गया है।

पुजारी के नाम 20 एकड़ जमीन

आयकर के छापों में जिन संपत्तियों का खुलासा हुआ है उनमें छोटे कारोबारियों और मंदिर के एक पुजारी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति मिली है। उनके नाम 20 एकड़ जमीन है। जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। बेनामी संपत्तियों के पीछे जो लोग है उनकी पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग की टीम अपने साथ दस्तावेजों के ढेर लेकर लौट गई है। विभाग के सामने 100 ऐसी प्रापर्टी सामने आ चुकी है जो बेनामी की बताई जा रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद संबंधित लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। इनमें प्रापर्टी के पुराने मालिक भी शामिल है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को भी इन संपत्तियों की सूची भेजकर उनका पुराना रिकार्ड मंगवाया गया है। पिछले 6-7 साल के दौरान जहां प्रापर्टी का लेनदेन किया गया। वहीं इस छापे के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जांच के बाद कई और नाम पर से पर्दा उठ सकता है।

भाजपा के दावे पर कांग्रेस ने किया पलटवार

40 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आंकड़ा फर्जी

2 दिन में कांग्रेस के 40 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली

मंत्री प्रद्युम्न तोमर के बयान का गोविंद ने दिया जवाब

भोपाल (विशेष प्रतिनिधि)

भाजपा ने दावा किया है कि ग्वालियर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय सदस्यता अभियान में बीते 2 दिन में 40 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि अभी तक 40 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। शाम तक ये आंकड़ा 60 हजार के पार होने का अनुमान हैं। प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि जो लोग सदस्यता ले रहे हैं उनकी सभी जानकारी हमारे पास है। सभी लोग अपने-अपने क्षेत्रों के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं।

भाजपा द्वारा कांग्रेस के 40 हजार कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किए जाने वाले दावे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद ने इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा भाजपा जिन लोगों के नाम ले रही है, उनसे उनकी बात हुई है वे लोग ग्वालियर ही नहीं आए न

दिग्गज नेताओं ने संभाली कमान

दरअसल, आगामी दिनों में प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर-चंबल संभाग में हैं। इसलिए वहां सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिन से ग्वालियर में ही है।

अभी 5 विस क्षेत्र बाकी

ग्वालियर में तीन से चल रहे सदस्यता अभियान का आज अंतिम दिन है। कार्यक्रम स्थल पर 16 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग सदस्यता लेने बुलाया जा रहा है। सोमवार दोपहर तक 11 विधानसभा के करीब 40 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। अभी 5 विधानसभा क्षेत्र इस इलाके के बाकी हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां के करीब 20 हजार से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता अभी पार्टी में और शामिल हो सकते हैं।

पूर्व महापौर भाजपा में शामिल

एक तरफ भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मेगा अभियान चलाकर पार्टी में शामिल कर रही है। वही, दूसरी ओर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ चुके भाजपाइयों को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। पिछले चुनाव में समीक्षा ने बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। समीक्षा को 21 हजार से अधिक वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी 121 मतों से चुनाव हार गए थे।

कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कांग्रेस ने की शिकायत

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चम्बल संभाग) केके मिश्रा ने आज कांग्रेस नेताओं और वरिष्ठ अभिभावकों के साथ जाकर थाना पड़ाव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्रसिंह को ग्वालियर के कलेक्टर और एसपी के खिलाफ चार थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज करने अलग-अलग आवेदन देकर उनसे पावती भी प्राप्त की। मिश्रा ने कहा कि इन दोनों ही अधिकारियों ने कोविड-19 को लेकर भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा 31 अगस्त 2020 तक जारी की गई गाइड लाइन और हर रविवार को होने वाले सख्त लॉकडाउन के परिपालन हेतु तयशुदा नियमों/निर्णयों का भी घोर उल्लंघन कर राजनैतिक दबाववश भाजपा को लाभ पहुंचाया है। मिश्रा आज प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष आरके भारद्वाज, वरिष्ठ अभिभावक संजय शुक्ला, जिला प्रवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेसजनों व वरिष्ठ अभिभावकों के साथ थाना पड़ाव पहुंचे और वहां मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्रसिंह को थाना पड़ाव, विश्वविद्यालय, गोले का मंदिर और झांसी रोड में एफआईआर दर्ज करने हेतु अलग-अलग आवेदन सौंपे।

राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन का किया शुभारंभ, नाथ बोले-

लॉलीपॉप पकड़ाने की राजनीति करती है भाजपा, जनता मांग रही हिसाब

भोपाल (विशेष प्रतिनिधि)

मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लॉलीपॉप और घोषणाओं की राजनीति करती है। लेकिन जनता अब उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही है।

उन्होंने कहा कि उपचुनाव तक बीजेपी सरकार रोज एक घोषणा करेगी। इन घोषणाओं का न कोई सिर और न ही कोई पैर है। इनमें गंभीरता भी नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर यह भी कहा कि राजीव जी ने देश को नई दिशा दी।

कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

वहीं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा है, वो हमला करें वो विपक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो कमलनाथ से चार हजार महंगाई भत्ते की घोषणा के बारे में पूछे।

विस प्रभारियों को दी जा रही ट्रेनिंग

इस मौके पर कमलनाथ ने राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन का शुभारंभ किया। इस प्लान से उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जोड़ने काम किया जा रहा है। इस मिशन के तहत विधानसभा प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर बूथ की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। बूथ पर जाकर कार्यकर्ता कांग्रेस की उपलब्धियों को जनता के बीच बता रहे हैं।

श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने की विभाग की समीक्षा

राज्य के सभी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार

संबल योजना और अधिक प्रभावी व सुगम बनाई जाएगी

भोपाल (विशेष प्रतिनिधि)

श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए रोजगार पोर्टल पर सरल हिन्दी भाषा में यूजर मेन्युअल एवं डेमो को दर्शाया जाए। जिससे सामान्य व्यक्ति को भी पंजीयन कराने में कोई कठिनाई न हो। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल की सुविधाओं को एप के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एनआईसी के सहयोग से सरलीकृत मोबाइल एप का निर्माण भी किया जाए। नीति आयोग द्वारा बनाये जा रहे उन्नति पोर्टल एवं अन्य राज्यों के पोर्टल का अध्ययन कर उनके आधार पर मध्यप्रदेश के रोजगार सेतु पोर्टल को अद्यतन किया जाए।

7 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन

उमाकांत उमराव ने बताया कि एक मार्च 2020 के बाद प्रदेश में लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन के लिए 27 मई से 06 जून, 2020 तक अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कार्य की प्रकृति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कुशलता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। कारखानों, वाणिज्यिकर स्थापनाओं, एमएसएमई, नियोक्ताओं, ठेकेदारों, प्लेसमेंट एजेंसियों, बिल्डरों इत्यादि जिन्हें श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

26 अगस्त से 11 सितम्बर तक चलेगा विशेष अभियान

सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के पेंशन प्रकरण होंगे हल

भोपाल। भोपाल संभाग के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण और स्वत्वों के निराकरण के लिए 26 अगस्त से 11 सितम्बर की अवधि में विशेष अभियान चलाया जाएगा। संभागायुक्त भोपाल कवीन्द्र कियावत ने संभाग के जिला कलेक्टर्स को अर्धशासकीय पत्र भेजकर उनके जिले के कार्यालयों में सेवानिवृत्त हुए सभी शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण एवं उनके स्वत्वों के निराकरण सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। संभागायुक्त ने कोषालय अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय/विभाग में पिछले 5 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों की सूची बनाकर चिन्हित कर उनके पेंशन प्रकरण, अवकाश नकदीकरण, जीपीएफ, डीपीएफ, जीआईएस एवं एफबीएफ आदि प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कियावत ने निर्देश दिए कि इस अभियान के बाद यदि किसी शासकीय सेवक के पेंशन प्रकरण निराकृत नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बालिका विद्यालय के शिक्षकों और छात्रावास स्टाफ के ऑनलाइन प्रशिक्षण का मंत्री ने किया शुभारंभ

सेन्टर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे छात्रावास

भोपाल (विशेष प्रतिनिधि)

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रज्जवला के तहत बालिका छात्रावासों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्टाफ को छात्रावास प्रबंधन एवं अकादमिक बिन्दुओं पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रदेश के 52 जिलों के 323 गर्ल्स हॉस्टल्स एवं 48 जिलों के 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मंत्री परमार ने कहा कि छात्रावासों को रहने-खाने की सुविधा के स्थान पर 'सेन्टर फॉर एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाए, जिससे छात्राओं का चहुंमुखी विकास हो। छात्राओं को इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लायक बनाने में यह अत्यन्त आवश्यक है। मंत्री परमार ने कहा कि कोरोना संकटकाल सभी के लिए चुनौती के साथ ही एक अवसर भी है। इस विकटकाल में विद्यार्थियों तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने कई नवाचार किए हैं। प्रज्जवला के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण से छात्रावासों में रहने वाली दूरस्थ गांव की छात्राओं के समग्र विकास में सहायता मिलेगी। यही छात्राएं आगे जाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी। मंत्री परमार ने कहा कि छात्रावासों में अच्छा वातावरण तैयार कर छात्राओं को अनुशासित जीवन, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने जैसी जीवन से जुड़ी कई आवश्यक चीजों

स्वच्छता का महत्व बढ़ा

प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी ने कहा कि छात्रावासों में सबसे वंचित वर्गों की बच्चियां आती हैं। छात्रावासों की अधिकतर छात्राएं प्रतिभाशाली होती हैं, इन्हें थोड़ा सहयोग मिले तो ये कई क्षेत्रों उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। हॉस्टल प्रबंधन से विद्यार्थी अनुशासित होकर शिक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं के अकादमिक उन्नयन के लिए स्टाफ को कौशल प्रदान करना है। छात्रावास के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता से जोड़ने के लिए भी कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्वच्छता से बेहतर कुछ नहीं। वर्तमान कोरोना संकटकाल में स्वच्छता का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

इन विषयों का मिलेगा प्रशिक्षण

2018-19 में प्रज्जवला कार्यक्रम के माध्यम से बोध शिक्षा समिति एवं जल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्रावास की छात्राओं के विकास के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसमें हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी विषयों पर राज्य की प्रचलित पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रशिक्षण देंगे।

दो पुलिस आरक्षकों को आजीवन कारावास, एक-एक हजार का दिया अर्थदंड

माही की गूंज, झाबुआ

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा पारित अपने निर्णय में फर्जी एनकाउंटर के दो आरोपी आरक्षक धीरेंद्र मंडलोई व रतनसिंह बारेला को 13 वर्ष पूर्व हुए फर्जी एनकाउंटर के आरोप में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन ने बताया कि, 2 जुलाई 2007 को रमेश उसकी पत्नी वेसाबाई और सौभान बारिया निवासी मेहंदी खेड़ा एक मोटरसाइकिल पर मेघनगर से झायड़ा जा रहे थे, उनके पीछे-पीछे फरियादी टीटू, कटिया एवं पेमा वसुनिया तथा जेलू दूसरी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। रास्ते में छोटा पुलिया चौराहे के पास दो पुलिस वाले एवं एक अनजान व्यक्ति रमेश को पकड़ने की कोशिश करने लगे तभी एक पुलिस वाले ने अपने पास की बंदूक से हवा में

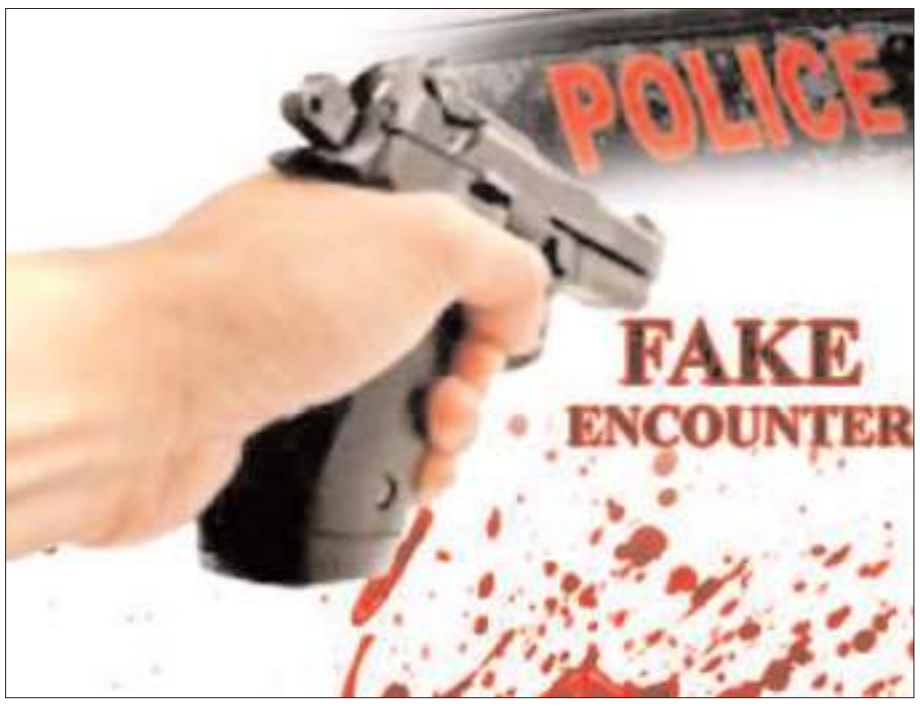

मामला: 13 वर्ष पूर्व फर्जी एनकाउंटर का

गोली चलाई, जो रमेश को लगी। बन्दुक की गोली लगते ही रमेश गिर गया। गोली चलाने के बाद दोनों पुलिस वाले मेघनगर की ओर भाग गए। फरियादी टीटू ने रमेश के पास जाकर देखा तो वह मर चुका था। इसके बाद फरियादी टीटू ने कटिया एवं जेलू के साथ झायड़ा जाकर रमेश के घर वालों एवं गांव वालों को घटना के बारे में बताया। फरियादी टीटू की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान उक्त दोनों आरोपी गण की पहचान की गई। विवेचना के पश्चात आरोपीगण धीरेंद्र मंडलोई एवं रतनसिंह बारेला के विरुद्ध धारा 302, 34 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र पूर्ण कर न्यायालय में पेश किया गया। लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आज पारित अपने निर्णय में फर्जी एनकाउंटर के दोनों आरोपीगण को दोषी घोषित कर आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनिट का मौन रखा

माही की गूंज, पेटलावद

तहसील पत्रकार संघ एवं अभिभाषक संघ द्वारा दिवंगत आत्मा को दो मिनिट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मेघनगर के वरिष्ठ पत्रकार व अभिभाषक संघ थांदला के अध्यक्ष सलीम शैरानी की माताजी श्रीमती हसमत नूर शेरानी, थांदला तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी शरीफ खान, झाबुआ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं जिलाध्यक्ष निर्मल मेहता के भाई राजेंद्र मेहता, करडावद के पटवारी खेमराज भाबर, रायपुरिया के पत्रकार देवीसिंह भूरिया के पिताजी मानसिंह भूरिया का स्वर्गवास हो जाने पर पेटलावद तहसील पत्रकार संघ एवं अभिभाषक संघ के द्वारा 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री अग्रवाल का आकस्मिक निधन

माही की गूंज, बामनिया

मंगलवार को बामनिया के लिए बुरी खबर आई, बामनिया निवासी

फक्कीरचंद अग्रवाल का आकस्मिक निधन बड़ोदा गुजरात मे हो गया, कुछ दिन पूर्व अचानक तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें बड़ोदा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी स्थिति सामान्य थी लेकिन सोमवार-मंगलवार की रात इनका निधन हो गया। फक्कीरचंद अग्रवाल मेडिकल संचालन शैलेन्द्र अग्रवाल के पिता थे, हँसमुख ओर मिलनसार श्री अग्रवाल हर किसी से प्रेम से मिलते ओर बात करते थे। कोरोना संक्रमण कोविड 19 के चलते गुजरात मे हॉस्पिटल में होने वाली किसी भी प्रकार की मौत के बाद गुजरात मे अंतिम संस्कार वही किया जाता है, ऐसे में स्व.फक्कीरचंद अग्रवाल का अंतिम संस्कार भी बड़ोदा में ही किया गया, जिसमें वहा मौजूद परिजन ही शामिल हो सके, बाकी परिवार और स्नेहीजनो ने घर से मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामेश्वर गर्ग, पत्रकार संघ बामनिया, माँ अम्बिका सेवा समिति बामनिया, मेडिकल एसोसिएशन आदि द्वारा श्री फक्कीरचंद अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की।

एक्सप्रेस वे में निकासी नहीं होने से कई खेत डूबे, खेतों में भर गया पानी भर जाने से फसलें हो गई चौपट

माही की गूंज भामल, नारायण पालरा

8 लेन के समीप जिन किसानों के खेत है, उनमें अधिक वर्षा होने के कारण व 8 वे निर्माण में नाला निकासी नही होने से किसानों की फसलों में पानी घुस गया, जिसमें कई किसानो की फसल भी चौपट हो गई, जिसकी शिकायत भी ठेकेदार को की लेकिन कोई सुनने को तैयार नही।

भामल के समीप से निकल रहा 8 लेन वे में किसान अनारसिंह पिता मानसिंह सोलंकी जाति राजपूत निवासी ग्राम

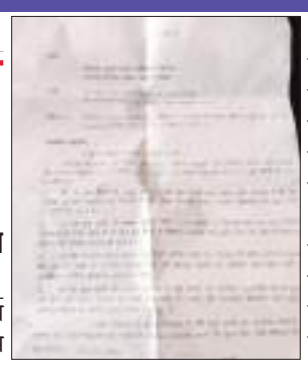

भामल ने बताया कि, मेरा सर्वे नं. 909 की भूमि है, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का काम कुछ दिनों से बंद है समय पर करवट व पानी निकासी के लिए प्ले स्ट्रक्चर नहीं बनाए, अभी हुई तेज बारिश से खेतों में पानी भर तालाब सा बन गया जिससे फसल लगभग खराब हो गई है, किसान ने एसडीएम से भी इस मामले में लिखित आवेदन भी पुर्व में दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई किसान ने, खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग भी रखी है बारिश में सबसे ज्यादा दिल्ली-मुंबई निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे किनारे वाले किसान परेशान हो गए है, जिनकी फसल नष्ट हो गई है।

सचिव को हटाने के लिये ग्रामीणों ने की शिकायत

माही की गूंज, खच्चरटोडी

मेघनगर जनपद की खच्चरटोडी पंचायत में सचिव पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदस्थ सचिव किशोर कटारा के मनमाने तरीके से काम करने के कारण ग्रामीणों ने जनपद सीईओ को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है, जिसमें खच्चरटोडी पंचायत से सचिव को हटाने कि मांग की। ग्रामीणों ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि, सचिव पंचायत कार्यालय नही खोलते है एवं किसी भी काम के लिए जब सम्पर्क किया जाता है तो सचिव संतुष्टि पूर्वक जवाब नही देते है। एवं पद का दुरूपयोग करते हुए दादागिरी पुर्ण रवैया अपनाते है। सचिव

के मनमाने तरीके से काम करने के कारण हम सब ग्रामीण काफी समस्या से जुझ रहे है। कार्यालय नही खोलने से कई बार छोटे-बडे काम समय पर नही हो पाते है। ग्राम में किए जा रहे निर्माण कार्य में भी काफी लापरवाही, अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

मुख्य चौराहे पर दुकान निर्माण के शुरू होते ही कार्य को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई

एसडीएम को सौपा कार्य बंद करने के लिए आवेदन

माही की गूंज, पेटलावद

ग्राम पंचायत बामनिया द्वारा नगर के मुख्य चौराहे को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से दुकान निर्माण करने का कार्य शुरू होते हीं नगर के कुछ लोगो ने कार्य पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए पेटलावद एसडीएम (आईएएस) को आवेंदन देकर कार्य को रोकने और निर्माण कार्य बिना अनुमति नियमों को ताक में रखकर करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओ का कहना है कि, पूर्व में ग्राम पंचायत बामनिया के द्वारा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हर्षल पंचोली से सर्वे नंबर 144 जो एमपीआरडीसी की अधिकरण क्षेत्र की भूमि है, उस जमीन पर पंचायत द्वारा दुकान निर्माण करने के लिए अनुमति चाही गई थी, लेकिन दुकान निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले ही आपत्ति दर्ज करवा दी गई थी। शिकायतकर्ताओ का कहना है कि तत्कालीन एसडीएम पेटलावद द्वारा मौका स्थल बामनिया आकर खुद के द्वारा निरीक्षण करके पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें दुकान निर्माण प्रकरण में स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत को आदेश किया था कि, इस जमीन का नक्शा स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, यह जमीन हाईवे क्रमांक 144 खतरनाक अंधे मोड़ पर सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत द्वारा दुकानों के लिए मांगी गई अनुमति का प्रकरण खारिज किया गया था।

राजनीति में उलझेगा दुकान निर्माण का मामला

जहा एक और शिकायतकर्ताओ ने कई प्रकार के नियमो को हवाला देते हुए पुराने आदेशो के साथ दुकान निर्माण के कार्य पर उंगली उठाई है, वही ग्राम पंचायत का कहना है कि, कार्य शुरू करने से पहले समस्त जरूरी कार्रवाई पूरी की है कुछ लोग राजनीतिक द्वेस्ता निकालने के लिए ग्राम के विकास में बाधक बन रहे हैं, कुल मिलाकर मामले में कार्य के शुरू होते ही राजनीति शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत सरपंच रामकन्या मखोड़ का कहना है कि, दुकान नही बनी हुई है तब भी लोग यहां अव्यवथित दुकाने लगाते है, हम दुकाने नियमानुसार बनाकर बाजार को व्यवस्थित कर रहे हैं, जिससे नगर का विकास होगा और नगर सुंदर दिखेगा यदी आपत्ति ली जाएगी तो उसका भी जबाब वरिष्ठ अधिकारीयो को विधीवत दिया जाएगा।

मामले की जाँच के बाद ही होगा कोई निर्णय

शिकायत के बाद नवागत एसडीएम शिशिर गेमावत द्वारा किसी प्रकार से फिलहाल कार्य रोकने का कोई आदेश नही दिया, बल्कि पूरे मामले को समझ कर कोई निर्णय लेने की बात कही है। नए एसडीएम के आने के बाद ही ये बड़ा मामला सामने आ गया हैं, जिसे नए अधिकारी कैसे हेंडल करते हैं ये भी देखने का विषय होगा।

फोटो 2 क्र 17, 18

दो माह में ही कृष्णा कंस्ट्रक्शन के घटिया निर्माण की खुली पोल...

सेमरी नदी के पुल के पास की सडक पहली ही बारिश में बही, दो माह पहले ही हुआ था निर्माण

माही की गूंज जामली, जितेंद्र राठौर

शुक्रवार-शनिवार को हुई तेज बारिश जिससे नदी नाले उफान पर रहे, वही तालाबो मे भरपुर पानी भर गया। इसी की चलते कई जगहो पर घटिया निर्माण की पोल भी खुली।

बेकल्दा-चारणकोटडा मार्ग का आधा-अधुरा निर्माण कार्य बारिश के पहले ही हुआ, उसके बाद से मार्ग का कार्य भी बाकी है। करोडो की लागत से बन रहे मार्ग का कार्य कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कृष्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा निम्न स्तर से किए जा रहे उक्त मार्ग के कार्य को पीडब्ल्युडी विभाग के जवाबदारो द्वारा देखी को अनदेखी की गई, नतिजन दो माह पुर्व ही बने उक्त मार्ग के सामरी नदी पर बनाई गई पुलिया बह गई।

ठेकेदार ने मनमानी कर सामरी नदी पर छोटी सी पुलिया बना दी, वही पुल के एक साईड मे दीवार भी नही बनाई। जिसके चलते शुक्रवार को हुई बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी। कम पाईप और छोटी दिवार होने के चलते पुल के पास दस फीट सडक खुद कर धुल गई। इस दौरान पुल पर कोई वाहन मौजुद नही था, जिससे कोई बडा हादसा नही हुआ। ग्राम के मोहन पंचोली, बजेसिंग बंजारा ने बताया कि, ग्राम पंचायत बेकल्दा-चारणकोटडा मार्ग पर स्थित पुलिया के निर्माण के समय ग्रामीणो ने भी संबंधित ठेकेदार के सुपरवाईजर को बताया था कि, पुल की दिवारे बनाए और

पाईप की संख्या भी बढाना होगी, चुंकि बारिश के दौरान नदी मे आने वाले पानी का चढाव ऊंचा रहता है, लेकिन उन्होने इस बात को नजर अंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ग्रामीणो को भुगतना पडेगा। विभाग के अधिकारीयो ने भी लापरवाही की और कंपनी ने भी पैसा बचाने के चक्कर मे घटिया निर्माण कार्य कर दिया।

रिटर्निंग वाल नही होने से बहा रोड
विभाग के स्टीमेंट में नही थी वाल

पानी के अधिक दबाव को देखते हुए पुल के पास एक रिटर्निंग वाल भी बननी थी, लेकिन विभाग ने सर्वे के दौरान इस वाल की जरूरत भी नही समझी और केवल पुलिया निर्माण कर दिया।

कार्य के इंजीनियर सुनील चौहान का कहना है कि, आवश्यकता अनुसार अब रिटर्निंग वाल का निर्माण करवाया जाएगा, कार्य के घटिया निर्माण को लेकर इंजीनियर चौहान का कहना है कि, निर्माण अधिक वर्षा होने के कारण बहा है, कार्य मे किसी प्रकार की अनियमित्ता नही की गई है।

वही ग्रामिणो को साहब की यह बात पता चली तो ग्रामिणो का कहना है कि, साहब अगर कार्य में अनियमित्ताए नही की गई तो आप इसकी उच्च स्तरीय जॉच करवाने का एक प्रतिवेदन अपने उच्च अधिकारीयो को दे और उच्च स्तरीय जॉच करवाइ जाए तो साहब की साठ-गाठ व ठेकेदार के द्वारा निम्न स्तर के किए गए कार्य का भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से उजागर हो जाएगा।

खेतो में पानी घुसने से खड़ी फसलें हुई बर्बाद

माही की गूंज, झकनावदा

लम्बे समय से भारी वर्षा की खेंच के बाद हुई भारी बारिश ने कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, शुक्रवार और शनिवार को झकनावदा और आसपास के क्षेत्र में लगातार हुई अत्यधिक वर्षा के कारण कई किसानों के खेतों में पानी घुस गया जिससे झकनावद क्षेत्र के किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। झकनावदा की मधु कन्या नदी में अत्यधिक वर्षा का पानी आने से आसपास के क्षेत्र कुंभाखेड़ी, बिजोरी, झकनावदा के करीब 100 से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने अधिक वर्षा से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग सरकार से की है।

फसलों में ब्लायट वायरस के प्रकोप से हुआ भारी नुकसान

फसलों को बचाने के उपयोग नही हो रहे कारगर, किसान चिंतित

माही की गूंज, रायपुरिया, उमाशंकर पाटीदार

रायपुरिया सहित बरवेट, जामली, रामनगर, रामगढ़, बनी, मोहनकोट, रताम्बा, सोयला पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान और समर्द्ध माना जाता है। यहां खेती में नए-नए प्रयोग करना तथा रिकॉर्ड उत्पादन करना किसानों के लिए आम बात रही है, लेकिन कुछ समय से खेती में विभिन्ना तरह के रोग और वायरस के प्रकोप के कारण किसान मुसीबत में फंस गए है। विभिन्ना तरह की फसलों में अब विषाणुजनित रोग आने लगे हैं और शक्तिशाली कीटों का प्रकोप होने लगा है। इस कारण मिर्च, टमाटर, मक्का, सोयबीन, आदि फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही हैं। इससे खेती में लागत बढ़ गई है और किसान कर्जदार होते जा रहे हैं। क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षो से ब्लायट, विल्ट नामक विषाणुजनित बीमारी का भयंकर प्रकोप हो रहा है। इस कारण सैकड़ों बीघा में लगने वाले कपास, मक्का आदि फसलें बर्बाद हो रही है। यह रोग होने पर फसल शुरुआत में तो अच्छी तरह बढ़ती है परंतु अच्छे खाद, पानी देने के बाद भी एकाएक सूख जाती है। पौधा पहले मुरझाता है और एक दो दिन में पूरा पौधा सूख जाता है। वास्तव में पौधे की जड़ में वायरस का प्रकोप होता है और इससे फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान फसल बचाने के लिए कई प्रयोग करता है किंतु उसे सफलता नहीं मिलती है। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी किसानों को कई तरह की रासायनिक दवाएं छिड़कने की सलाह देते है, लेकिन इस के बाद भी फसल बचाना असंभव हो जाता है।

वायरस की चपेट में आई फसल ओर बर्बाद हुए खेत के साथ किसान

ब्लायट, विल्ट के कारण हुए कर्जदार

क्षेत्र में नगद फसल लेने वाले किसान विल्ट व अन्य वायरसजनित रोगों से फसल खराब होने के कारण प्रतिवर्ष आर्थिक रूप से कई नुकसान उठाते है। खेती करने के लिए वे सहकारी समितियों और बैंकों से क्रॉप लोन लेते हैं, परंतु फसल खराब होने के कारण लोन वापस नहीं कर पाते और डिफाल्टर हो जाते है। किसान रोग पर नियंत्रण करने की उम्मीद में महंगे से महंगे कीटनाशक खरीदकर उसका अंधाधुंध छिड़काव करते है। इसका उनकी भूमि और उनके परिवार के स्वास्थ्य पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इतना सब करने के बाद भी विल्ट पर काबू पाना किसानों के लिए असंभव हो गया है। विल्ट के अलावा कई अन्य फसलों के संक्रामक रोग क्षेत्र में तेजी से फैल रहे है। जैसे टमाटर में ब्लाइट, सोयाबीन और उड़द में यलो मोजेक, मिर्च में ब्लेक राड वायरस जैसे खतरनाक रोग पनप रहे है। इससे इन फसलों की खेती किसानों के लिए बहुत कठिन हो गई है। इन रोगों पर नियंत्रण करने के लिए किसानों आवट, फेम, कोराजन और मोनो प्रोटो फास जैसे घातक कीटनाशक खेतों में डालना पड़ रहे है। इससे खेती की लागत बढ़ गई है। इन रोगों के प्रकोप के कारण भी किसान बहुत नुकसान उठा रहे है। कइयों ने तो अपनी फसलें ही बदल दी। कुछ ने खेती करना छोड़ दिया। फसलों में फैलने वाले इन रोगों से किसान तंग आ गए है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फसल को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, क्योंकि आधुनिक कृषि विज्ञान द्वारा सुझाए उपायों को अपनाकर किसान थक चुके है नई नई दवाइयां उपयोग में लाकर भी किसान वाइरस की चपेट में आई फसलों को बचा पाने में सफल नही हो पा रहा है।

संपादकीय

कांग्रेस में गांधी होने का मतलब

सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना नहीं चाहतीं, लेकिन अभी कोई सर्वसम्मत विकल्प भी नहीं है। उन्होंने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने की सलाह दी है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद से बातचीत की है और कुछ उन वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठी का जवाब भी भेजा है, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिख कर 'ऊपर से नीचे तक' आमूल परिवर्तन की मांग की थी। बेशक कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ पहली बार ऐसी अभूतपूर्व आवाज उठाई गई। चिट्ठी लिखने वालों में कांग्रेस की सभी पीढ़ियों के प्रतिनिधि हैं। ये तमाम नेता वे हैं, जिन्होंने कांग्रेस सरकारों के दौरान सत्ता-सुख भोगा था या पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं अथवा नेहरू-गांधी परिवार को ही 'कांग्रेस' मानते आए हैं। चिट्ठी लिखने वालों में पांच पूर्व मुख्यमंत्री, कई कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य, मौजूदा सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। इन 23 कांग्रेस नेताओं की मांग है कि पार्टी को पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व चाहिए। वह स्थायी भाव वाला सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व राजनीतिक तौर पर दिखना भी चाहिए और सक्रिय भी होना चाहिए। पार्टी की सर्वोच्च नीति-निर्धारक इकाई-कांग्रेस कार्यसमिति-के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए और मनोनयन बंद हो। हालांकि चिट्ठी लिखने वालों ने प्रत्यक्ष तौर पर नेहरू-गांधी परिवार को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की है और न ही गैर-गांधी कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का सुझाव दिया है। हालांकि गैर-गांधी अध्यक्ष वाली बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में कही थी, लेकिन पार्टी में आमूल बदलाव के मायने क्या हैं? गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं होगा, तो फिर दूसरा चेहरा किस नेता का है, जिस पर सर्वसम्मति बन सके। चिट्ठी के जरिए जो सामने आया है, उसके मद्देनजर आमूल परिवर्तन इसलिए जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा कालखंड की सबसे बड़ी और गंभीर राजनीतिक चुनौती हैं। उन्हें टक्कर देने वाला कोई भी नेता कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। युवा वर्ग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के पक्ष में मतदान किया। साफ है कि कांग्रेस देश के युवाओं का भरोसा खो चुकी है और पार्टी का परंपरागत जनाधार और समर्थन का आधार भी ढह रहा है। मध्य वर्ग में भी कांग्रेस के प्रति मोहभंग की स्थिति है, लिहाजा पार्टी के अस्तित्व को बचाने की चिंता है। सवाल है कि वरिष्ठ नेता पार्टी की चिंता कर रहे हैं या अपनी संसदीय राजनीति को बरकरार रखने को चिंतित हैं? मसलन-राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। उनका जम्मू-कश्मीर से दोबारा निर्वाचन असंभव है, क्योंकि अभी तो वहां चुनाव ही अनिश्चित हैं और राज्यपाल शासन जारी है। ऐसे ही कई बड़े और बुजुर्ग नेता हैं, जिनका निर्वाचन फंसा हुआ है। संगठन में भी कोई सम्मानजनक पद खाली नहीं है। चूंकि नए कांग्रेस अध्यक्ष की बहस शुरू हो गई है, लिहाजा बुनियादी सवाल तो यह है कि यदि नेहरू-गांधी परिवार का सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होगा, तो पार्टी की धुरी कौन बनेगा, जिसके इर्द-गिर्द पार्टी चल सके। कहने को कुछ नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन वे मोदी को चुनौती देने लायक साबित नहीं हो सकते और न ही पार्टी में आमूल बदलाव लाने की 'क्रांति' कर सकते हैं। यही कारण है कि अधिकतर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के नेतृत्व के पक्षधर हैं या राहुल गांधी को दूसरा विकल्प मान रहे हैं। बयानबाजी भी उसी तर्ज पर जारी है। वैसे भी करीब एक साल पहले राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को 'अंतरिम अध्यक्ष' बनाया गया था। इस अंतराल में नया अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन कांग्रेस में इतने गंभीर निर्णय यूं ही नहीं लिए जाते। कांग्रेस ने लोकसभा के लगातार दो चुनाव हारने के बाद चिट्ठी के रूप में प्रतिक्रिया देने में इतना लंबा वक्त निकाल दिया। कांग्रेस में अब बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच भी विभाजन की स्थिति साफ दिखाई देती है, जो बीते दिनों एक बैठक के दौरान सोनिया गांधी के सामने ही मुखर हो गई थी। युवाओं की सोच और महत्वाकांक्षा भिन्न है, लेकिन बुजुर्ग भी अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्या यह विभाजन ही पार्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? इसका विश्लेषण कार्यसमिति की बैठक के बाद करेंगे।

जनसंख्या-धर्मग्रंथ एवं राष्ट्रधर्म

डॉ. मोक्षराज

न कोई देश केवल बाइबिल के आधार पर चल रहा है और न केवल कुरान या पुराणों के बल पर। सच तो ये है कि विज्ञान ने आधुनिक जीवन के ढंग को अत्यधिक प्रभावित किया है।

कट्टर से भी कट्टर मुस्लिम, ईसाई या हिंदू व्यक्ति मोबाइल फोन, टीवी, बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ का उपयोग कर ही रहा है और इन सबका आविष्कार उनके किसी पैगंबर, ईश्वर पुत्र या किसी अवतार ने विगत 2000 वर्षों में तो नहीं किया है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अपना एक विशाल संविधान है। अत- वहाँ सभी नागरिकों के उत्थान के लिए धर्म को निरपेक्ष मानते हुए ही नीतियों का निर्धारण होना चाहिए अर्थात् जबतक भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष रहे तबतक किसी भी धर्म, मत या संप्रदाय को ध्यान में रखकर नीतियाँ नहीं बननी चाहिए। तभी वह सही मायने में निरपेक्षतावादी भी कहलाएगा।

यदि भारत की बहुसंख्यक जनता अपने ऐतिहासिक तथ्यों और धर्मग्रंथों के आधार पर भारत को चलाना चाहती तो उसे रामायण, महाभारत, वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर नीतियाँ बनाने की ज़िद पर अड़े रहना था, जैसे कि- ङ्घरामायणङ्घ में बताया है कि महाराज सगर इक्ष्वाकु वंशीय थे तथा महाराज भगीरथ, दशरथ एवं श्रीराम के पूर्वज थे। महाराज सगर की एक पत्नी केशिनी से एक पुत्र तथा दूसरी पत्नी सुमति से विशेष विज्ञान तकनीक द्वारा 60000 संतानें हुईं। इसी प्रकार ङ्घमहाभारतङ्घ के अनुसार धृतराष्ट्र के 102 पुत्र थे। गान्धारी के दुर्योधन, दुःशासन आदि 100 पुत्र तथा एक पुत्री दुःशला थी। ङ्घपुराणोंङ्घ के अनुसार यदि हम भगवान श्री कृष्णचन्द्र जी के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो उनकी 8 रानियाँ थीं- रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा। इनसे 80 पुत्र-पुत्री पैदा हुए। ऋग्वेदीय ङ्घऐतरेय ब्राह्मणङ्घ में वर्णन है कि महर्षि विश्वामित्र के भी 100 पुत्र थे तथा उन्होंने एक पुत्र शुनःशेप को अजीगर्ति से गोद भी लिया था। उनके विद्रोही पुत्र तुर्वसु से ही कालांतर में यवन पैदा हुए, यह अलग कथा है। ङ्घऋग्वेदङ्घ में भी ङ्घइमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु। दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि।ङ्घ मंत्र से 10 संतान उत्पन्न करने का निर्देश मिलता है। जिसके संदर्भ में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि गृहस्थ दम्पति 10 संतान तक उत्पन्न करे किन्तु यदि वह दरिद्र है तो बच्चों के लालन-पालन को ध्यान में रखते हुए समृद्धि के अनुरूप ही संतान पैदा करे।

इन कुछ उदाहरणों के आधार पर यदि पूरे भारत के लोग आर्य (हिंदू) अपने अपने इष्ट, देवता, पूर्वज या भगवान के नाम पर अपनी आस्था व धर्मग्रंथ की दुहाई देते हुए 10 संतान से लेकर 60 हज़ार तक प्राकृतिक रूप से या विज्ञान का सहारा लेकर अपने पूर्वजों की भाँति टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोन के रूप में संतान पैदा करने लग जाए तो भारत के सीमित भूभाग पर केवल पाँच वर्ष में ही अन्न, पानी, आवास व अन्य सुविधाओं का अकाल पड़ जाएगा। किंतु वे ऐसा दुराग्रह इसलिए नहीं करते हैं, वे अपने राष्ट्र की उन्नति को पहले स्थान पर तथा अपनी धार्मिक निष्ठा को दूसरे स्थान पर रखते हैं। जब वे अपने धर्मग्रंथ, आस्था व पूर्वजों की परंपराओं से समझौता कर सकते हैं तो दूसरे वर्गों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। उनका यह विचार कमज़ोरी नहीं है बल्कि इसी सोच से भारत को समृद्धि तथा भारत के संविधान को ताकत मिलती है। अपने देश के समग्र विकास के लिए इसी प्रकार की उदारता एवं राष्ट्रनिष्ठा की आवश्यकता है। अन्य मतवादियों को भी अपनी रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा तभी वे भारत के उत्थान के लिए बराबर के भागीदार माने जा सकेंगे। अनेक शोधकर्ताओं का मानना है कि सन् 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश में जब अनेक मत, मज़हब व सम्प्रदायों की तार्किक समीक्षा की गई तो उसके परिणामस्वरूप अनेक मज़हब व संप्रदायों की पुस्तकों में अनेक संशोधन हुए। आज भी इसी प्रकार के उदार भाव की आवश्यकता है। भारत के समग्र विकास की दिशा में सबका विकास हो रहा है। सबको बिना किसी मत-मज़हबी भेदभाव के गैस बिजली, आवास, शौचालय एवं स्वास्थ्य व जीवन रक्षा की दृष्टि से आयुष्मान भारत आदि योजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 'मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू।' कितना अच्छा हो कि भारत सरकार की ओर से संचालित समग्रतावादी, दूरगामी तथा विकासोन्मुखी पहल ङ्घसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासङ्घ की भावना को मोटी चमड़ी वाले तथाकथित धर्माचार्य भी अपने व्यवहार में लाएँ। वे इस दिशा में सहयोग करके ङ्घसबका विश्वासङ्घ जीत सकेंगे। हमें भारत को सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए तथा रामराज्य लाने के लिए भगवान श्रीराम व माता सीता के समान ङ्घहम दो हमारे दोङ्घ का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(लेखक वाशिंगटन डीसी में भारतीय संस्कृति शिक्षक हैं।)

किसान बनाएगा आत्मनिर्भर भारत की राह

डॉ. राकेश राणा

असली भारत गांवों में बसता है। देश के करीब छः लाख गांव में बसे लघु-सीमांत किसान अपने खून-पसीने की मेहनत से कृषि उद्यम कर देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का सफल किर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार 67.04 प्रतिशत किसान परिवार सीमांत किसान हैं। जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन का स्वामित्व है। उनमें भी 17.93 प्रतिशत छोटे किसान परिवार हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर जमीन का मालिकाना है। वहीं 10.05 प्रतिशत परिवारों के पास मात्र 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है जिन्हें अर्द्ध-मध्यम श्रेणी का किसान माना जाता है और मध्यम श्रेणी में चार से दस हेक्टेयर के किसान आते हैं। 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले मात्र लगभग 5 प्रतिशत किसान ही देश में हैं। यह परिदृश्य साफ बताता है कि भारत लघु-सीमांत किसानों का विशाल देश है। भारतीय ग्रामीण समाज में छोटी जोत वाले आम गरीब कृषक परिवार ही ज्यादा है। देश में कृषि जोत का आकार लगातार घटता जा रहा है। परिणामस्वरूप आय कम और बढ़ते खर्चों से ग्रामीणों का जीवन स्तर निरन्तर गिर रहा है।

कोरोना वैश्विक महामारी से उपजे आर्थिक संकट से देश को उबारने में भी ग्रामीण भारत ही महती भूमिका निभायेगा। सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने का काम देश का किसान वर्ग ही करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए जो देश की जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है, निर्धारित किया गया। देश में लॉकडाउन के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एवं किसान तथा मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। जिसका उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही मील का पत्थर बनेगा। इससे सभी सेक्टरों की कार्य क्षमता व दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी आयेगी। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुणा करना है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए एग्रीकल्चर

इंफरास्ट्रक्चर हेतु 11 लाख करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था की गयी है। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की एवं मछली उद्योग के लिए दो हजार करोड़ रुपए आवंटित किए है। पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित हो सके इस हेतु 15,000 करोड़ रुपए की अरिरिक्त व्यवस्था इस पैकेज में की गयी है। ग्रामीण किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रवृत्त किया जाय इस दृष्टि से हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए की अरिरिक्त व्यवस्था अभियान के तहत की गई है। साथ ही पांच सौ करोड़ रुपए की धनराशि फल-सब्जियों के खाद्य प्रसंस्करण हेतु आप्रेशन गीन के विस्तार हेतु रखी गई है। वहीं मनरेगा के तहत ग्रामीणों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में चालीस हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है वह हासिल कैसे किया जाय? एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि देश में खेती छोड़कर पलायन करने वाले ग्रामीणों में सर्वाधिक संख्या सीमांत किसानों की है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में जब किसान वर्ग खेती-बाड़ी से विमुख हो रहा है। कैसे सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाए। इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में सरकार को समाज के साथ मिलकर कुछ प्रेरक मॉडल कृषि क्षेत्र के लिए विकसित करने की जरूरत है। कृषि की छोटी-छोटी जोतों को जोड़कर प्रयोगधर्मी आकार के कृषक समूहों का निर्माण करने जरूरत है। जो सहकारी खेती का एक सामाजिक मॉडल बन सकता है। जिसमें जमीनों को संगठित किया जाय और खेती में कुछ नए ढंग के प्रयोग किए जाएं। कृषि को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसके लाभ विभिन्न स्तरों पर तो दिखायी देंगे ही, किसानों की आय दोगुनी करने में भी यह मॉडल बहुत कारगर सिद्ध होगा।

सहकारी खेती यानी छोटे किसानों का आपस में मिल-जुलकर खेती करना है। यह खेतीबाड़ी करने का ग्रामीण भारत में परम्परागत सामाजिक मॉडल है। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और हरियाणा में साझी खेती करने के इस मॉडल को 'डंगवारा' कहा जाता रहा है। परम्परागत भारतीय समाज की इस सहयोगात्मक व्यवस्था को केरल और आंध्र प्रदेश में महिला कृषक समूहों के जरिए सरकार ने आधुनिक रूप प्रदान किया है। केरल सरकार का 'कुडुम्बश्री' कार्यक्रम इसी पैटर्न पर 10 किसानों को जोड़कर एक समूह बनाता है और खेती के लिए लीज़ पर ज़मीन उपलब्ध कराता है। यह केरल में बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास हेतु रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर जीवन स्तर सुधारने तक यह अहम् भूमिका निभा रहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में महिलाओं के समूह को-आपरेटिव खेती कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में पारस कृषि संस्थान ऐसे प्रयोगों का नया मॉडल खड़ा कर रहा है। देश के सीमांत किसानों की अधिकांश समस्याओं का हल खेती की इस साझा प्रणाली में छिपा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वहां रोजगार और विकास की सर्वाधिक गुंजाईश तो है ही दूसरा भारत का कृषि क्षेत्र जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनका समाधान भी यह अभियान कर सकता है। भारतीय गांव जैविक खेती के महान प्रयोग स्थल बनकर उभर सकते हैं। जिससे किसान का सशक्तिकरण तो होगा ही, देश और दुनिया के सम्मुख खड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां भी कम होंगी। अधिक पैदावार और शीघ्र उत्पादन के लिए फसलों में जो अंधाधुंध रसायनिक खाद, कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। नतीजतन मिट्टी, जल, हवा और खाद्यान सब प्रदूषित हो रहे हैं। जिनके जरिए बीमारियां मानव शरीर में पहुँच रही हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीणों की आय का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है और उनकी आय व जीवन स्तर दोनों निम्न बने हुए हैं।

मानव स्वास्थ्य का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर सीधा पड़ता है। इसलिए पर्यावरणीय और स्वास्थ्य की दृष्टि के साथ आर्थिक नजरिए से भी जैविक खेती समाज को सशक्त बनाने का एक कारगर माध्यम है। कृषि उत्पादों और उनसे संबंधित लघु-कुटीर उद्योग गावों में लगेंगे तो ग्रामीणों की आय में गुणात्मक वृद्धि होगी। जैविक उत्पाद से आय बढ़गी और लागत खर्च कम होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका आधार बने और इसी में दोनों की सफलता भी निहित है। आत्मनिर्भर भारत की राह किसान ही बनाएगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जब कोरोना का उफान तो बेफिक्र क्यों इंसान !

लेखक, ऋतुपर्ण दवे

केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए मनमाफिक अधिकारों के बजाए कोरोना पर वन नेशन वन डायरेक्शन का फॉर्मूला अपनाया जाए. सोशल डिस्टेंसिंग, सभी जरूरी जगहों पर मास्क पहनने, देश भर में दूकानों के बन्द और खुलने का एक सा समय, सप्ताहान्त व साप्ताहिक कर्फ्यू जैसी सख्ती के लिए पूरे देश में एक से नियम हों ताकि विविध नियमों का भय और संशय न रहे।

कोविड अस्पतालों की बेहतरी के लिए देश में सभी सेन्टरों को सीसीटीवी सर्वेलॉन्स के एक प्लेटफॉर्म पर लाकर तुरंत एक सेण्ट्रल मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित की जाए जो नामुमिकन नहीं है.

दरअसल कोरोना को लेकर अब लोगों में तरह-तरह की भ्रान्तियां बहुत तेजी से घर करती जा रही हैं.निश्चित रूप से यह बेहद चिन्ताजनक और भयावह है. उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह कि भारत में पहली बार एक दिन में 30 जुलाई को कोरोना मरीजों की संख्या 50 हजार पार कर 52 हजार 123 क्या हुई जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है. इसके बाद तो जैसे हर रोज संख्या बढ़ोत्तरी की होड़ सी लग गई.पिछले एक हफ्ते से तो लगातार 60 से 70 हजार संक्रमितों के मामले सामने आते रहे. लेकिन इसी सप्ताहांत शनिवार देर रात इसका भी रिकॉर्ड टूट गया और एक दिन में कुल मामले 70 हजार को पार कर गए. इसे हल्के से लेना न केवल बेहद घातक होता जा रहा है बल्कि इसके गंभीर, नकारात्मक और दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं. आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग कोरोना को लेकर एकदम बेफिक्र से होते जा रहे हैं? वह भी तब, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ लगातार चेता रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय भी बता रहा है. सभी राज्य सतर्कता को लेकर नित नए आदेश निकाल रहे हैं. सब जानते हैं कि कोरोना इस सदी की घातक वैश्विक महामारी तो भारत की राष्ट्रीय आपदा है.

69 दिनों के लॉकडाउन का दौर देश पहले देख चुका है. अब कोई भी लॉकडाउननहीं देखना चाहता क्योंकि इससे लाखों नौकरियां चली गईं, न जाने कितने छोटे-बड़े रोजगार, धंधे बन्द हुए. बावजूद इसके लोगों के दिमाग से कोरोना का डर आखिर क्योंखत्म हो रहा है?यह चिन्ताजनक है! हाल ही में उप्र के दो कैबिनेट मंत्रियोंकी मृत्यु गई. 9 दूसरे मंत्री संक्रमित हुए. देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी संक्रमण के साथ गंभीर हैं. जबकि गृहमंत्री अमित शाह भी कोरोना की चपेट में आए. मप्र में तो मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री गिरफ्त में आ चुके हैं और सिलसिला जारी है. दूसरे कई प्रदेशों में भी कमोवेश यही हालात हैं. मंत्री, विधायक, विशिष्ट, अतिविशिष्ट किसी को भी कोरोना ने नहीं बख्शा. केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री पद नाइक की हालत कोरोना संक्रमण से बेहद गंभीर हो गई थी. गोवा सरकार ने भी माना हैवो मौत के मुंह से लौटे हैं. फिर भी लोग लापरवाह क्यों हो रहे हैं?

समझना होगा कि आखिर हुआ क्या जो लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो रहा है? इस सच को समझने से नुमाइन्दों और हुक्मरानों को भी परहेज नहीं करना चाहिए. हो सकता है कि कमीं कहें या चूक या फिर अनदेखी जो भी हो उसे सुधार लिया जाए और एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार थामी जा सके.दुनिया का भूगोल तो बदला नहीं जा सकता. देश, शहर, गांव की दूरियां वही रहेंगी. हां कुछ घटा है तो इंसानों का आपसी संपर्क जिसे मोबाइल और सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया और आपसी विश्लेषणों के दौर तर्क-कुतर्क का मौका दिया. कितनी ही सच्ची-झूठी धारणाएं, अवधारणाएँ भी बनी, बिगड़ी होंगी. लॉकडाउन में कठोरता, अनलॉक में ढ़ील के अपने-अपने मायनों से ही लापरवाहियों केउपजने का सिलसिला चल पड़ा. पहले केन्द्र की इकलौती गाइड लाइनथी. अबराज्यों के अपने निर्देशों हैं.कई राज्यों में डीएम को जरूरत के मुताबिक जिले में आदेश का अधिकार है तो डीएम अपने-अपने अनुविभागों में एसडीएम को जिम्मेदारी दे चुके हैं.नतीजन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से भी भारत में कोरोना महामारी पर राज्यों की अपनी-अपनी ढ़पली, अपना-अपना राग जैसी स्थिति बन गई. बस यहीं से लोगों में भ्रान्तियां भी फैलीं और ऐसी भ्रान्ति सोशल मीडिया पर कैसी-कैसी क्रान्ति लातीहै पूछिए मत. वाट्स एप यूनिवर्सिटी का सच सबको पता है. कोरोना को लेकर भी कुछ यही हुआ. वह अपनी अंधी रफ्तार बढ़ता रहा. इस बीच रही सही कसर तमाम कोविड अस्पतालों की दुर्दशा, साधारण दवाओं से इलाज का भ्रम और इलाज में लापरवाहियों के लीक तमाम वायरल वीडियो जिसमें इंसानी अंगों के निकालने की मनगढ़ंत कहानियों ने पूरी कर दी. शायद इन्हीं सब से डर जाता रहा. वैक्सीन के आभाव में इम्युनिटी पर जोर का वाजिब फण्डा प्रशंसनीय है.

सच कहा जाए तो होम आइसोलेशन, क्वारण्टीन, कंटेनमेण्ट एरिया के जहां-तहां नित नए बदलते नियमों से भी आम जनमानस में डर कमा और भ्रम बढ़ा. माना कि हालातों के मद्देनजर यह जरूरी था लेकिन उससे जरूरी यह था कि जनसामान्य को मानसिक रूप से संक्रमण के पहले जैसे बल्कि और भी बढ़े खतरे से आगाह कराते हुए राहत कीवजहें बताकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटेशन की जरूरत पर सख्ती से अमल काकड़ा संदेश देना था. यही नहीं हुआ. यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी खूब फॉरवर्ड और शेयर हुए जिन्हें कईकोरोना पीड़ितों ने मौत से पहले बनाकर जारी किया था. बावजूद इन सबके कोरोना को लेकर बेफिक्रीहैरान करती है. अब चाहे व्यापारी हों,नागरिक या फिर अधिकारी ही क्यों न हो मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की लापरवाही, सार्वजनिक स्थलों पर थूंकना या गंदगी फैलाने पर जुर्माना प्रशंसनीय है. लेकिन दुख तब होता है जब एक आम आदमी यह कीमत लाठियों से पिटकर चुकाता है.कठोरता का मतलब पिटाई तो नहीं. समझाइश से हल निकलता है, निकला है.

बीते शनिवार की देर रात कोरोना संक्रमण ने एक दिन में 70 हजार पार कर नया रिकॉर्ड रचाजबकि कुल संक्रमितों की संख्या साढ़े 30 लाख के करीब पहुंच गई. यहबेहद गंभीर चेतावनी है. ऐसे में रिकवरी रेट के बढ़ते आंकड़ों से वाहवाहीलूटसंक्रमण केभय को दबाने की कोशिशभी ठीक नहीं.दूसरे देशों के आंकड़ों से रिकवरी कीतुलना कर हम जनसामान्य को अच्छा संदेश जरूर देते हैं. लेकिन यह भूल जाते हैं कि केवलकोरे संदेशों और आंकड़ों की बाजीगरी से लड़ाई जीत नहीं पाएंगे. निदान के रास्ते पर बढ़ना होगा और कोरोना से बचाव, सेहत की सुरक्षा, जनजीवन के लिए जरूरी गतिविधियों को बिना संक्रमण की जद में आए जारी रखने वाले प्रयासों पर ज्यादा ध्यान देना होगा. जाहिर है अब लॉकडाउन की स्थिति दिखती नहीं. हाँ, ऐसी सख्तियों की सख्तजरूरत है ताकि लोग खुद ही होशियार रहें. केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए मनमाफिक अधिकारों के बजाए कोरोना पर वन नेशन वन डायरेक्शन का फॉर्मूला अपनाया जाए.सोशल डिस्टेंसिंग, सभी जरूरी जगहों पर मास्क पहनने, देश भर में दूकानों के बन्द और खुलने का एक सा समय, सप्ताहान्त व साप्ताहिक कर्फ्यू जैसी सख्ती के लिए पूरे देश में एक से नियम हों ताकि विविधनियमों का भय और संशय न रहे. कोविड अस्पतालों की बेहतरी के लिए देश में सभी सेन्टरों को सीसीटीवी सर्वेलॉन्स के एक प्लेटफॉर्म पर लाकरतुरंत एक सेण्ट्रल मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित की जाए जो नामुमिकन नहीं है. सभी बड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालोंमें सीसीटीवी होते हैं जिन्हें सहज उपलब्ध तकनीक से जोड़नेशनल सर्वेलान्स सिस्टम बनाना होगा ताकि देश के किसी भी अस्पताल की व्यवस्था-अव्यवस्था कोरेण्डमली कभी भी देखा, जाना जा सके. इससे भयवश ही सही व्यवस्था सुधरेगी. एक बार फिर कोविड-19 युध्द पर सरकारी तंत्र की कसावट के साथ पुलिसिंग को भी पूर्ववत सख्ती के लिए तैयार करना होगा ताकि सार्वजनिक स्थान, हाट, बाजार, चल रहे सार्वजनिक परिवहन और कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में नियमों का सुनिश्चित पालन हो. उससे भी बड़ा यह हो कि बढ़ते आंकड़ों के बावजूद कोरोना के भय को लेकर हाल ही मे हुई लापरवाहियों को बिना किसी टीका-टिप्पणी के दुरुस्त किया जाए. जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लिए जाएं. अब तक लापरवाही से ही सही आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आगे न बढ़ पाए क्योंकि कोरोना का असर पूरे देश में है और यह कोई मायने नहीं रखता कि कहां ज्यादा कहां कम. रिकॉर्ड बताते हैं कब कहां कोरोना ब्लास्ट हो जाए किसी को नहीं पता होता, जब होता है तब हड़कंप मच जाता है. वैसे भी इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश को एक जुट होना होगा. यह तभी होगा जब केन्द्र के निर्देशों में राज्य काम करें ताकि पूरे देश में कोरोना की एक जैसी, एक साथ लड़ाई लडी जाए. आपसी भेद, मतभेद न दिखें ताकि कोरोना की मजूबत हो चुकी चैन को इस बार तोड़ ही दिया जाए. यह नहीं तो कम से कम कोरोना की रफ्तार को ही रोके रखा जाए क्योंकि वैक्सीन करीब है और उसके बाद जंग जीतना तय है. रफ्तार को रोकना ही किसी बड़ी जंग जीतने से कम नहीं होगा.चुनौती आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं. बस जरूरत है हर कोई एक बार फिर कोरोना की चुनौती समझे और मात देने को आगे आए।

विलक्षण नेतृत्व - अनोखा आंदोलन

नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना के 35 वर्ष

डॉ सुनीलम, लेखक

नर्मदा बचाओ आंदोलन 35 वर्ष का प्रौढ़ हो गया है युवावस्था के आंदोलन की कहानियां अब किवदंतिया बन चुकी है इसके बावजूद आंदोलन में यौवन का उत्साह ,उमंग,आक्रोश ,संकल्प आज भी दिखाई पड़ती है ।तीसरी पीढ़ी अब नेतृत्व में प्रमुख भूमिका में दिखलाई पड़ती है। आंदोलन की प्रेरणा से देश में हजारों जन आंदोलन खड़े हुए है और प्रमाणिक जन आंदोलनकारी तैयार हो चुके हैं।

35 वर्षों से समर्पित होकर अनवरत संघर्ष करने वाली मेधा पाटकर अब देश और दुनिया की आइकॉन बन चुकी है। जिसका सम्मान पार्टियों, जातियों, धर्मों, भाषाओं, लिंगों और इलाकाई पर्वग्रहों के ऊपर उठ कर लगभग सभी के द्वारा किया जाता है। प्रशासन,पुलिस से जुड़े अधिकारी और विभिन्न सरकारों के विधायक ,सांसद ,मंत्री ,मुख्यमंत्री उनकी विलक्षण प्रतिभा के कायल है। संघर्ष, रचना और विचार का काम एक साथ करने वाले नेतृत्वकर्ता कम पाए जाते हैं। मेधा जी देश के ऐसे गिने-चुने लोगों में से है,जिन्होंने कोरोना काल में भी सरकारों द्वारा अतिथि श्रमिकों पर किये जा रहे अन्याय, अत्याचार,भ्रष्टाचार और भेदभाव को सड़कों पर जाकर चुनौती दी है। हमारे जैसे तमाम साथी उनसे स्थाई तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने का कहते हैं, लेकिन उनका स्थाई जवाब होता है कि आप देश की चिंता कीजिए, मेरी नहीं।

परंतु किसी भी आंदोलन के 35 वर्ष बाद उसका मूल्यांकन किया जाना लाजमी है। ऐसा करते समय महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि क्या कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति किसी आंदोलन को खड़ा करके 35 वर्ष तक चला सकता है? मुझे लगता है वह खींच तो सकता है,लेकिन संगठन को जीवंत रखते हुए चला पाना अत्यंत कठिन कार्य होता है। आमतौर पर आंदोलनों के बारे में कहा जाता है कि यदि आंदोलन अपनी मांगे मनवाने में सफल होता है तो भी खत्म हो जाता है तथा यदि असफल होता है तो भी खत्म हो जाता है। आंदोलन की उम्र कुछ वर्षों की ही होती है,वह भी मुद्दा आधारित आंदोलन तो और भी अल्पकालिक होता है। लोगों को लगता था कि सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकने और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आंदोलन चल रहा था। बांध बन गया संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नर्मदा बचाओ आंदोलन की खासियत है। दूर से देखने वालों को लग सकता है कि यह आंदोलन केवल मेधा पाटकर जी के इर्दगिर्द खड़ा हुआ है लेकिन यह वास्तविकता नहीं है ।आंदोलन के निर्णय गांव-गांव में बिखरे हुए कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम वासियों को साथ बिठाकर किए जाते हैं। इस तरह जो निर्णय नर्मदा घाटी के ग्राम वासियों के द्वारा होते हैं, उनकी पुष्टि कार्यकर्ताओं की खुली बैठक में की जाती है, उन्हीं फैसलों के सार्वजनिक घोषणा करने का काम मेधा जी द्वारा किया जाता है। लेकिन गत 35 वर्षों में किसी ने कोई भी प्रेस नोट मेधा पाटकर जी के नाम से जारी होते हुए नहीं देखा या सुना होगा। उसमें आंदोलन के सभी प्रमुख साथियों के नाम होते हैं अंतिम नाम मेधा जी का । मेधाजी नर्मदा बचाओ आंदोलन की ना संयोजक है, ना अध्यक्ष ।अन्य संगठनों से हटकर आंदोलन का कोई पदाधिकारी नहीं है। सही मायने में यही जन आंदोलन है। आंदोलन की जान उसके समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्होंने तन,मन, धन लगाकर पुलिस दमन,फर्जी मुकदमे सहकर भी आंदोलन को इस स्थिति में पंहुचाया है। आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके कार्यकर्ता वैचारिक तौर पर प्रशिक्षित है। वे वैकल्पिक विकास की नीतियों पर बहुत स्पष्टता के साथ बात रखते हैं तथा 24 घंटे आंदोलन के लिए समय और साधन देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी घाटी में आंदोलन के कार्यक्रम में गया होगा, उसने देखा होगा कि आंदोलन के कार्यकर्ताओं के घरों से ही बनवाकर बाहर से आने वाले समर्थकों को खाना खिलाया जाता है तथा कार्यकर्ताओं के घर ही रूकवाया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर जितने किताबें लिखी गईं , जितनी फिल्में बनी, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उतना देश ने किसी दूसरे आंदोलन के बारे में नहीं देखा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के चलते मेधा जी को दुनिया के तमाम बड़े पुरस्कार मिले हैं लेकिन कभी आपको पढ़ने नहीं मिलेगा कि फलाने फलाने पुरस्कार पाने वाली मेधा पाटकर ने कहा कि, जिसका मतलब यह है कि उनकी पहचान किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं है। आंदोलन में बाबा आमटे जैसे विख्यात समाजसेवियों को प्रभावित किया। उन्होंने अपना अंतिम समय नर्मदा किनारे बिताया। ख्याति प्राप्त अरुंधति रॉय जब नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी तब उन पर वही अवमानना का प्रकरण दर्ज किया था, जो अब प्रशांत भूषण पर किया है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की पैरवी विगत 35 वर्षों से लगातार प्रशांत भूषण, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे राजेंद्र सच्चर, संजय पारिख, राजीव धवन जैसे देश के ख्याति प्राप्त वकील करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खुद मेधाजी नर्मदा बचाओ आंदोलन की पैरवी करती है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन देश का ऐसा अनोखा आंदोलन है जिसके चलते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम फैसले दिए हैं जिससे देश के करोड़ों विस्थापितों को लाभ हुआ है। जमीन के बदले जमीन हो या एक एक विस्थापित को साठ लाख रू देने का फैसले हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अंग्रेजों के जमाने के भूमि अधिग्रहण कानून की बदलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा से मुंबई में घर बचाओ,घर बनाओ आंदोलन भी इस तरह से चला , जिसके चलते मुंबई के लाखों गरीबों के मकान टूटने से बचे हैं तथा लाखों के घर बसे हैं।

आंदोलन की नेत्री के तौर पर मेधा पूरे देश में लोकप्रिय है लेकिन मैंने उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से भी अधिक केरल राज्य में देखी है ।मेधा पाटकर जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जनांदोलनों के समन्वय की जरूरत को समझा तथा अन्य जनांदोलनों के साथ मिलकर 30 साल पहले जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बनाया जिसके साथ देश के 350 जनांदोलन जुड़े हुए हैं। भूमि अधिकार आंदोलन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के गठन मे भी नर्मदा बचाओ आंदोलन की अहम भुमिका रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोधी नहीं रहा। गुजरात सरकार ने तो कई दशकों से उनके प्रवेश पर ही पाबंदी लगा रखी है। यह बात अलग है कि गुजरात के कांग्रेसियों को अब अपनी गलती का अहसास हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मेधा पाटकर उनकी घोषित दुश्मन है। कोर्ट में उन पर विदेशी धन लेने के आरोप लगाकर मुकदमा चलाए गए। अहमदाबाद में हमला किया गया लेकिन हर बार वे सभी आरोपों से दोष मुक्त होकर निकली हैं । नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़वा दी लेकिन आज तक वे डूब क्षेत्र के ढाई सौ गांव को डुबोने में कामयाब नहीं हुए हैं ।

आज 35 साल के बाद भी आंदोलन पूरी घाटी क्षेत्र में जारी है।

आज 35 वर्ष पूरे होने पर घाटी के 500 से अधिक युवाओं ने गांव में स्कूल बंद होने के कारण जो बच्चे पढ़ नही पा रहे हैं उन्हें पढ़ाने का संकल्प लिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जीवन शालाओं से 5000 से भी अधिक बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं, जो आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थकों के तौर पर चट्टान की तरह खड़े हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन को इस स्थिति में पहुंचाने में लाखों समर्थकों की भूमिका अहम रही है ,जिन्होंने देश भर में नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थक समूह बनाकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का गत 35 वर्षों में जब जब जरूरत पड़ी है तब तब साथ दिया है। मैं गत 25 वर्षों से मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। जब भी आंदोलनों के कार्यक्रमों में घाटी जाता हूँ, दो आपत्तियां जरूर दर्ज कराता रहा हूँ। एक यह कि %राजनीति धोखा है,धक्का मारो मौका है% का नारा बेमानी है,क्योंकि राजनीति से ही सब कुछ तय होता है। बांध बनाने का फैसला भी राजनीतिक फैसला है। राजनीति विकास की दिशा तय करती है।

दूसरा मैं मेधा पाटकर जी द्वारा आमरण अनशन किए जाने के सैद्धांतिक तौर पर खिलाफ हूँ। सीमित समय के उपवास या क्रमिक भूख हड़ताल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आजकल जो मेरी आपत्ति है वह आंदोलन से नहीं, मेघा जी द्वारा कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां का पालन नहीं करने से है। सभी आपत्तियों के बावजूद मैं मानता हूं कि मेधा पाटकर और आंदोलन से देश और दुनिया भर के सजग नागरिकों को बहुत कुछ सीखने मिला है इसीलिए सभी को एक बार नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में जाने की सलाह सभी को देता हूँ।

हिंदी में बोलने पर सजा ?

लेखक - डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। द्रमुक की नेता कनिमोझी ने मांग की है कि सरकार उन्हें तुरंत मुअत्तिल करे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो उनका भाषण हिंदी में नहीं सुनना चाहे, वह बाहर चला जाए। वे देश के आयुर्वेदिक वैद्यों और प्राकृतिक चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। इस सरकारी कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 300 लोग भाग ले रहे थे। उनमें 40 तमिलनाडु से थे। जाहिर है कि तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन इतने लंबे अर्से से चला आ रहा है कि तमिल लोग दूसरे प्रांतों के लोगों के मुकाबले हिंदी कम समझते हैं। यदि वे समझते हैं तो भी वे नहीं समझने का दिखावा करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए ? कोटेचा को चाहिए था कि वे वहां किसी अनुवादक को अपने पास बिठा लेते। वह तमिल में अनुवाद करता चलता, जैसा कि संसद में होता है। दूसरा रास्ता यह था कि वे संक्षेप में अपनी बात अंग्रेजी में भी कह देते लेकिन उनका यह कहना कि जो उनका हिंदी भाषण नहीं सुनना चाहे, वह बाहर चला जाए, उचित नहीं है। यह सरकारी नीति के तो विरुद्ध है ही, मानवीय दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रणेता थे लेकिन गांधीजी और लोहियाजी क्रमशः 'यंग इंडिया' और 'मेनकांइड' पत्रिका अंग्रेजी में निकालते थे। उनके बाद इस आंदोलन को देश में मैंने चलाया लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरु विवि और दिल्ली में विवि में जब व्याख्यान देता था तो मेरे कई विदेशी और तमिल छात्रों के लिए मुझे अंग्रेजी ही नहीं, रुसी और फारसी भाषा में भी बोलना पड़ता था। हमें अंग्रेजी भाषा का नहीं, उसके वर्चस्व का विरोध करना है। राजेश कोटेचा का हिंदी में बोलना इसलिए ठीक मालूम पड़ता है कि देश के ज्यादातर वैद्य हिंदी और संस्कृत भाषा समझते हैं लेकिन तमिलभाषियों के प्रति उनका रवैया थोड़ा व्यावहारिक होता तो बेहतर रहता। उनका यह कहना भी सही हो सकता है कि कुछ हुड़दंगियों ने फिजूल ही माहौल बिगाड़ने का काम किया लेकिन सरकारी अफसरों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। यों भी कनिमोझी और तमिल वैद्यों को यह तो पता होगा कि कोटेचा हिंदीभाषी नहीं हैं। उन्हीं की तरह वे अहिंदीभाषी गुजराती हैं। उनको मुअत्तिल करने की मांग बिल्कुल बेतुकी है। यदि उनकी इस मांग को मान लिया जाए तो देश में पता नहीं किस-किस को मुअत्तिल होना पड़ेगा। कोटेचा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी बढ़िया नहीं बोल पाता हूं, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। जब तक देश में अंग्रेजी की गुलामी जारी रहेगी, मुट्ठीभर भद्रलोक भारतीय भाषा-भाषियों को इसी तरह तंग करते रहेंगे। कनिमोझी जैसी महिला नेताओं को चाहिए कि वे रामास्वामी नाइकर, अन्नादुराई और करुणानिधि से थोड़ा आगे का रास्ता पकड़ें। तमिल को जरुर आगे बढ़ाएं लेकिन अंग्रेजी के मायामोह से मुक्त हो जाएं।

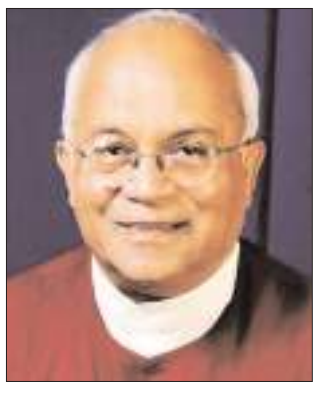

न्याय पालिका पर सवालिया निशान क्यों.. ?

लेखक-ओमप्रकाश मेहता

भारत प्रजातंत्र चार स्तंभों पर अवस्थित है- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व अघोषित स्तंभ खबरपालिका। मूलतः प्रारंभिक तीन स्तंभों को लेकर ही स्वस्थ व चिरजीवी प्रजातंत्र की कल्पना की गई थी, किंतु पिछले सत्तर सालों में इनमें से दो स्तंभ विधायिका व कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा व ईमानदारी से नहीं कर पाए, जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र के निवासी भारतीयों की आशा विश्वास का केन्द्र न्यायपालिका ही बन गई और इस आशा विश्वास की न्यायपालिका ने ईमानदारी से रक्षा भी की, किंतु अब पिछले कुछ समय से न्यायपालिका के प्रति जो आस्था व विश्वास की मजबूत मीनार खड़ी थी, उसमें कई जगह दरार नजर आने लगी और अब वह दरार दिनों-दिन न सिर्फ चौड़ी होती जा रही है, बल्कि उसके कारण प्रजातंत्र के महल को खतरा भी नजर आने लगा है। यद्यपि विधायिका के सदस्यों की तरह न्यायपालिका के न्यायाधीशों को भी नियुक्ति के समय ईमानदारी, निष्ठा व संविधान की शपथ दिलाई जाती है, किंतु अब धीरे-धीरे विधायिका व उसकी सहायक कार्यपालिका इतनी निरंकुश होती जा रही है कि उसने न सिर्फ स्वतंत्र न्यायपालिका को गलत तरीकों से प्रभावित करने की कोशिशें की, बल्कि कई बार इस स्तंभ पर भी अपना अधिकार जताने की कोशिशें की, जबकि हमारे संविधान में तीनों स्तंभों की पृथक-पृथक कार्यक्षेत्र सीमाएँ तय की गई है तथा प्रत्येक स्तंभ को कहा गया है कि वह दूसरे स्तंभ के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, पिछले सत्तर सालों में सत्ताधीशों ने अपनी सुविधा के अनुरूप संविधान में सवा सौ से भी अधिक संशोधन कर दिए हो उन्हीं सत्ताधीशों ने हर समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने का भी प्रयास किया, यही नहीं संविधान की भावना के खिलाफ उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ देकर न्याय खरीदने की कोशिशें भी की गई और इसी कारण अब न्यायपालिका की निष्पक्षता विवादों के घेरे में आई, जिसका ताजा उदाहरण पीएम केयर्स फण्ड को लेकर ताजा फैसला और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर मानहानि का प्रकरण है। पीएम केयर्स फण्ड व प्रशांत भूषण द्वारा कथित मानहानि ये दोनों प्रकरण राजनीति के दायरें के है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया साफ नजर आया है। पीएम केयर्स फण्ड वाले मामले के पीछे कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी दल है, तो प्रशांत भूषण के पीछे डेढ़ दर्जन सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश व तीन सौ के करीब देश के वरिष्ठ अधिवक्ता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र सौंपा है।

अब जहां तक पीएम केयर्स फण्ड का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च 2020 को इसकी स्थापना कर कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए इस कोष की स्थापना की, जिसे खर्च करने का पूर्ण दायित्व प्रधानमंत्री को सौंपा गया, इसका प्रतिपक्षी दलों ने विरोध किया व इसके खर्च करने का दायित्व एक विधिवत कमेटी गठित कर उसे सौंपने की मांग की। अर्थात् प्रतिपक्षी की इस मांग के पीछे प्रधानमंत्री की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना रहा होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। ऐसी ही कुछ चर्चा प्रशांत भूषण के मामले को लेकर है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी कांग्रेस से जुड़े है। यहाँ मेरा इरादा माननीय सुप्रीम कोर्ट व उसके माननीय न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली पर कोई आक्षेप लगाना कतई नहीं है, किंतु यह तो एक कटु सत्य है कि देश की आवाम का विधायिका व कार्य पालिका की तरह अब न्यायपालिका से भी धीरे-धीरे विश्वास कम होता जा रहा है। इस पर समय रहते सभी पक्षों को गंभीर चिंतन कर दुरूस्त करने का व न्यायपालिका के प्रति पूर्ववत आस्था कायम करने के प्रयास करना चाहिए।

जिले के समस्त न्यायालय हुए आईएसओ अवार्ड प्राप्त

देश में बड़वानी जिला पहला जिला बना जिसके समस्त न्यायालय भवन है आईएसओ

माही की गूंज, बड़वानी

जिले के 3 न्यायालय परिसर सेंधवा, अंजड़, राजपुर को भी अब आईएसओ अवार्ड मिल जाने से जिले के अब समस्त 5 न्यायालय परिसर आईएसओ अवार्ड से नवाजे जा चुके है। अब बड़वानी जिला, देश में पहला जिला बन गया है, जहॉ के समस्त न्यायालय भवन आईएसओ अवार्ड प्राप्त है।

जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे से प्राप्त जानकारी अनुसार उनके कार्यकाल में सर्वप्रथम सन् 2018 में खेतिया न्यायालय परिसर को आईएसओ अवार्ड मिला था, उसके पश्चात सन् 2019 में जिला न्यायालय परिसर बड़वानी आईएसओ अवार्ड से नवाजा गया था। अब सन् 2020 में जिले के शेष 3 न्यायालय परिसर सेंधवा, अंजड़, राजपुर को भी आईएसओ अवार्ड मिल जाने से बड़वानी जिला देश में पहला जिला बन गया है, जिसके समस्त न्यायालय परिसर आईएसओ अवार्ड से पुरस्कृत है।

कांग्रेस सरकार गिराने का जवाब जनता उपचुनाव में देगी

युथ कांग्रेस बैठक में राष्ट्रीय सचिव इशिता सेढ़ा ने कहा

माही की गूंज, खरगोन।

प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले युथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने एवं नई उर्जा का संचार करने के लिए मंगलवार को यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेढ़ा सनावद पहुंची। यहां विधायक सचिन बिरला, रवि जोशी सहित यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सेढ़ा का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस दौरान बैठक में सेढ़ा ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस.भाजपा का नहीं जनता का चुनाव हो गया है। क्योंकि जिस तरह खरीद.फरोख्त कर भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरा दी उसका जवाब अब जनता पूछेगी। इस चुनाव में भाजपा को उसके द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए की गई हरकत का जवाब मिल जाएगा। कार्यकर्ताओं से सेढ़ा ने अपील करते हुए कहा कि टिकट किसी को भी मिलें, कार्यकर्ता प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम करेंगे को निश्चित हमें जितने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सीख देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना जरूरी है, क्योंकि वह पार्टी के लिए मेहनत करता है। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस को मजबुत करने के लिए ग्रामस्तर तक नियुक्तियां पर जोर दिया। इस दौरान शिव तिवारी, सचिन जोशी, दीपक डंडीर, पुष्कर्राज सिंह, गणपति परसाई, पियुष रघुवंशी, विक्रांत दांगी, समीर खान, सुल्तान भुट्टो, अभिनव आर्य, अंतिम खांडे, प्रशांत भालसे सहित जिलेभर के जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद थे।

1 लाख 19 हजार श्रमिकों को मिला मनरेगा में रोजगार

माही की गूंज, खरगोन

देश की सबसे बड़ी रोजगार प्रदाय करने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में 20 जून से अब तक 1 लाख 19 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदाय किया जा चुका है। इतने मजदूरों को 40 करोड़ 75 लाख 29 हजार 770 रूपए की राशि का भुगतान उनके खातों में किया गया। कोविड-19 के कारण अपने-अपने रोजगार से छूटे नागरिकों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहीं है। जिला पंचायत सीईओ गौरव बेनल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश के 116 चयनित जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू की गई। इसमें मप्र के 24 जिलों में से खरगोन में कई महत्वपूर्ण परिणामकारी कार्य किए गए। खासकर ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना से जल संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से उपयोगी कार्य हुए है, जो निश्चित तौर पर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

40 करोड़ से अधिक का किया भुगतान

25 हजार से अधिक श्रमिकों को मिला काम

कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने ऐसे जिले, जहां पर 25 हजार से अधिक प्रवासी मजदूर आएं हो, उनके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लागू किया था। इस अभियान में खरगोन जिले में 30 हजार 83 प्रवासी मजदूर आएं। इनमें 25 हजार श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदाय किया गया। इस योजना के अंतर्गत खेत, तालाब, कूप निर्माण, वानिकी और वृक्षारोपण के कार्य कराएं गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व पीएम सड़क योजना ग्रामीण के तहत कार्य किए गए। इन सभी के अलावा 14वें वित्त के तहत पंचायत भवन, सीसी रोड़ एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 200 समुदाय स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है। मनरेगा पीओ श्याम रघुवंशी ने बताया कि मप्र शासन द्वारा चलाए गए विशेष श्रम सिद्धी अभियान में 16 हजार 687 परिवारों के नए जॉब कार्ड बनाकर 59 हजार 128 सदस्यों को 1 अप्रैल के बाद जोड़ा गया।

कलेक्टर ने ग्राम धवली पहुंचकर देखी शासकीय योजनाओं की मैदानी स्थिति

माही की गूंज, बड़वानी

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज ने बुधवार को जिले के सबसे दूरस्थ ग्राम धवली पहुचकर ग्रामवासियों से चर्चाकर विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

एसडीएम करेंगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सत्यापन

धवली के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम के छोटेसिंह से चर्चाकर जाना कि, उनके बीपीएल राशन कार्ड पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निःशुल्क खाद्यान्न कब-कब मिला। इस पर हितग्राही की जानकारी एवं मौके पर उपस्थित सेल्समेन की जानकारी में भिन्नता मिलने पर कलेक्टर ने मौके पर ही उपस्थित एसडीएम सुश्री तपस्या परिहार को निर्देशित किया कि, वे टीम बनाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभान्वितों का सत्यापन रेकार्ड से करवायेंगी और अगर सत्यापन के दौरान कोई अनियमित्ता मिलती है तो तत्काल सेल्समेन के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगी। इस दौरान कलेक्टर ने मौके पर ही उपस्थित सहायक खाद्य अधिकारी भुरमल बामनिया को भी निर्देशित किया कि वे अपने स्तर से भी रेकार्ड एवं आवंटन का परीक्षण कर प्रतिवेदन एसडीएम को प्रस्तुत करेंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की दी जानकारी

ग्राम पहुंचे कलेक्टर श्री वर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज ने ग्रामीणो को बताया कि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को नियमित मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त अप्रैल से नवम्बर माह तक प्रत्येक माह प्रति सदस्य 5 किलो के मान से निःशुल्क खाद्यान्न मिलना है। अगर पात्र लोगो को इस योजना का लाभ मिलने में कोई परेशानी आ रही हो तो वे इसकी शिकायत एसडीएम या उन्हें उनके व्हाटसअप नम्बर 7587980400 पर कर सकते है।

डाक्टर को दिया नियमित आने का निर्देश

कलेक्टर के जानकारी लेने पर ग्रामवासियों ने ग्राम की दो एएनएम सुश्री मालती अस्के और निर्मला चौहान के कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हुए बताया कि, इनकी सेवाओं से सभी ग्रामवासी खुश है। किन्तु ग्राम में पदस्थ डाक्टर मोहित मोतियानी नियमित ग्राम में नही आते। जिसके कारण ग्रामवासियों को परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस पर कलेक्टर ने मौके पर ही उपस्थित डाक्टर मोहित मोतियानी को निर्देशित किया कि, वे ग्राम में नियमित रूप से आकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

पात्र लोग तहसीलदार को करें आवेदन, जुड़ेंगे नाम

चौपाल पर ग्रामवासियों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि, अगले माह से सभी लोगो को पात्रता पर्ची मिलने लगेगी । जिससे उन्हें खाद्यान्न लेने में परेशानी नही आयेगी। वही ऐसे पात्र जिनका नाम अभी बीपीएल सूची में नही है, वे लोग तहसीलदार को आवेदन करें। जिससे उनके पात्रता का सत्यापन किया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि, जिले में 43 सौ परिवार ऐसे है, जिन्होने विगत 6 माह से राशन नहीं लिया है, इनके नाम हटाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस कार्यवाही के दौरान जितने लोगो के नाम हटेंगे, उतने ही नवीन पात्र लोगो के नाम जोड़े भी जायेंगे।

सामुदायिक शौचालय एवं सीसी रोड़ का किया निरीक्षण

कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम में बन रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं हो रहे सीसी रोड़ के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने मौके पर कार्य कर रहे मजदूरों से उन्हें मिल रही मजदूरी की जानकारी प्राप्त की । साथ ही मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव बबलू चौहान एवं सरपंच जगन बर्डे को निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश भी दिए।

ग्रामवासियों की मांग पर दिया परीक्षण कराने का आश्वासन

जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की बार्डर पर स्थित धवली ग्राम पहुंचने पर कलेक्टर से ग्रामवासियों ने महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की सीमा बनाने वाली आनेर नदी पर पुल बनाने, ग्राम में स्थाई पुलिस चौकी की स्थापना कराने, ग्राम के मुख्य मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटवाने, यात्री प्रतिक्षालय को कब्जा मुक्त कराने, 35 वर्ष पूर्व निर्मित उपमण्डी को प्रारंभ करवाने की मांग करने पर कलेक्टर ने उपस्थितो को आश्वस्त किया कि, उक्त मांगो का परीक्षण करवाते हुए यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करवाई जायेगी।

कपास सीजन का मुर्हूत शुक्रवार को

माही की गूंज, खरगोन

इस वर्ष कपास सीजन का मुर्हूत कपास मंडी प्रांगण में शुक्रवार को दोपहर सवा 12 बजे किया जाएगा। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि, वर्तमान में कपास की आवक प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन सोलह श्राद्ध के बाद मुर्हूत नहीं होने से शुक्रवार को ही कपास सीजन का मुर्हूत किया जा रहा है। कपास सीजन का मुर्हूत क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल एवं क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी द्वारा किया जाएगा। मुर्हूत के पश्चात शुक्रवार को ही मंडी पुनः बंद कर दी जाएगी। कपास की आवक प्रारंभ होते ही कपास मंडी प्रारंभ की जाएगी। मंडी सचिव किरार ने समस्त किसानों से आग्रह किया कि, कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए एक वाहन के साथ वाहन चालक एवं एक व्यक्ति ही मंडी प्रांगण में कपास विक्रय के लिए लाएं।

कलेक्टर से पहले संयुक्त कलेक्टर करेगी शिकायतों की समीक्षा

माही की गूंज, खरगोन

अब कलेक्टर से पहले संयुक्त कलेक्टर विभिन्न शिकायतों की समीक्षा करेंगी। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि, जिला स्तर पर प्रति सप्ताह सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक में समय सीमा के लंबित पत्र, संभाग, संचालनालय, शासन से प्राप्त लंबित अर्द्धशासकीय पत्र, पीजी हेल्पलाईन, सीएम हेल्पलाईन, सीएम मॉनिट, मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन, मंत्री, सांसद, विधायक की ओर से प्राप्त लंबित तथा जन सुनवाई के दौरान दर्ज शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। अब इन शिकायतों की समीक्षा प्रति शुक्रवार को संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नेहा शिवहरे अपने स्तर से करेगी। इस दौरान जिन लंबित पत्रों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलती है, तत्संबंध में अधिकारीवार सूची तैयार कर प्रति सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक में समीक्षा कराई जाएगी।

स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित मास्क के विक्रय केंद्र का एसडीएम ने किया शुभारंभ

माही की गूंज, खरगोन

मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड भीकनगांव के अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए स्व-सहायता समूह के द्वारा मास्क, हैंड सेनीटाईजर एवं पीपीटी कीट निर्माण कार्य किया जा रहा है। भीकनगांव विकासखंड के ग्राम साईंखेड़ी में संचालित नर्मदा आजीविका स्व-सहायता समूह के द्वारा अभी तक 7 हजार से अधिक मास्क तैयार किए है।

मास्क विक्रय एवं मांग की जा रही है उसके अनुसार मास्क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को भीकनगांव एसडीएम राहुल चौहान द्वारा ग्राम साईंखेड़ी में स्व-सहायता समूह नर्मदा आजीविका समूह का मास्क निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया और स्व-सहायता समूह को आगे लाते हुए और सशक्त करने के लिए भीकनगांव नगर परिषद में एक मास्क वितरण केंद्र की शुरुआत की गई। एसडीएम श्री चौहान द्वारा सभी शासकीय विभागों को निर्देशित किया है कि स्व-सहायता समूह के द्वारा निर्मित मास्क खरीदकर अपने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में वितरित करें।

भीकनगांव विकासखंड में 4 समुह है कार्यरत

आजीविका मिशन की परियोजना अधिकारी श्रीमती सीमा निगवाल ने बताया कि भीकनगांव विकासखंड में वर्तमान में 4 स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें नर्मदा आजीविका समूह साईंखेड़ी, सामर बाबा आजीविका समूह कांझर, राधिका समृद्धि आजीविका समूह अगरिया, एकता आजीविका समूह दौड़वा शामिल है। इनमें से साबर बाबा आजीविका समूह कांझर के द्वारा अभी तक 100 पीपीटी कीट का निर्माण किया जा चुका है। वहीं लगभग 17 हजार मास्क का निर्माण एवं वितरण किया जा चुका है। इस अवसर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ एवं नगर परिषद सीएमओ उपस्थित रहे।

जन जागरूकता के लिए कलेक्टर और अधिकारी करेंगे मार्च पास्ट

माही की गूंज, खरगोन

कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखते हुए लोगों में मास्क व सेनिटाईजर तथा फिजिकल दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से आज गुरूवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी पुलिस अमले व विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मार्च पास्ट करेंगी। मार्च पास्ट में लगभग 100 पुलिस, अधिकारी व कर्मचारी रहेंगे। यह मार्च पास्ट बस स्टैंड स्थित गौर पेट्रोल पंप से प्रारंभ होगा, जो श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहा होते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, जहां समापन होगा।

जाहिर सूचना

मकान वार्ड क्र 6 रायपुरिया-बामनिया रोड़ पर आई माता आर्ट के सामने स्थित, पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उक्त भूमि सहित मकान हमारी पक्षकारा श्रीमती सुंदर बाई पति स्व. धनराज चौधरी के एकमात्र की मालिकी व अधिपत्य का है। उक्त सम्पत्ति हमारी पक्षकारा को उनके पति स्वर्गीय धनराज चौधरी की मृत्यु पश्चात पहली पत्नि होने के नाते उतराधिकार मे प्राप्त हुई है। अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था का उक्त सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक अधिपत्य नहीं है। हमारी पक्षकारा की जानकारी में यह बात आई है कि, कोई अन्य स्त्री और उसके बेटे मिलकर पेटलावद में किसी अन्य विक्रेता को सम्पत्ति अपनी मालिकी की बताकर, विक्रय करने या पगड़ी देने हेतु प्रयासरत है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त भवन भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो वह कार्यवाही हमारी पक्षकारा पर बंधनकारक नहीं होगी तथा विधि अनुसार शून्य होगी। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हमारी पक्षकारा द्वारा धोखाधड़ी व भादवि की अन्य धाराओं के अन्तर्गत फौजदारी एवं दिवानी प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

विजेंद्र जादौन एडवोकेट पेटलावद
शासकीय होस्पिटल परिसर पेटलावद 457773
7974355164

जल मग्न हुए नदी-नाले

माही की गूंज, कुंदनपुर कृष्णपालसिंह ठाकुर

लम्बे इंतजार के बाद हुई बारिश से नदी-नाले, तालाब सभी जल मग्न हो गए वही काफी नुकसान भी हुआ है। राणापुर के कुंदनपुर में चन्द्रभागा और मोद नदी भी जल मग्न हो गई। इस वर्ष की यह तेज बारिश के बाद नदी-नाले ऐसे जल मग्न हो गए की हर कोई एक बार नदी किनारे जाकर तेज बहते पानी को देखकर देखने वालो का मन प्रफुलित हो गए।

क्षेत्र में गर्मियों में सूख चुके जंगल के पेड़ भी इस बारिश से हरे-भरे हो गए हैं। जंगली जानवरों व पशुओं के लिए जंगल में चारा-पानी का इंतजाम हो गया।

वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने चरम पर होती है। इसके साथ ही प्रकृति की यह मनोहारी घटा देखकर हम सभी (मनुष्य) भी आनन्दित, उत्साहित एवं मोहित हो जाते है। मनोहारी एवं मनमोहक हरियाली से भरपुर प्राकृतिक परिदृष्य सभी को आकर्षित करता है।

उपभोक्ताओं को लग रहा बिजली बिल का झटका

कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था खराब, मंद पड़े व्यापार, आखिर आम आदमी कैसे भरें भारी भरकम बिल

माही की गूंज, मेघनगर भूपेंद्र जैन

बारिश के मौसम में बिजली की खपत कम होने के बावजुद भी उपभोक्ताओं को मनमाने तरीके से बिजली के बिल दिए जा रहे है, लोग इससे परेशान हो गए है। उपभोक्ताओ का कहना है कि, विभागीय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे है, खपत कम होने के बाद भी अधिक राशि के बिल आ रहे है, यह बात समझ से परे है। हाल ही में बिजली विभाग ने जुलाई माह के विद्युत बिल उपभोक्ताओं को जारी किए हैं वे अत्यधिक व मनमानी राशी के होकर सामान्य बिल के मुकाबले कई गुना अधिक राशि के बिल थमाए गए है, जिन्हें भरने में असमर्थता व्यक्त करने पर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं के यहां इतनी अधिक खपत ही नहीं है जितनी राशि के विद्युत मंडल द्वारा बिल दिये जा रहे है। कई लोग तो कच्चे व किराए के मकानों में निवास कर रहे हैं जिनके यहां विलासिता तो दूर की बात आवश्यक विद्युत उपकरण तक नहीं है, इनमें बडी संख्या में अत्यधिक गरीब उपभोक्ता भी हैं जो कि, एक ही कमरे में रहकर जैसे-तैसे जीवन यापन कर रहे है, उनको भी काफी अधिक राशि के बिल थमा दिए गए। यही स्थिति मध्यमवर्गीय व उच्चवर्गीय उपभोक्ताओं की भी है, इन्हें भी विभाग द्वारा भारी भरकम बिल थमाए गए है जिससे लोगो में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।

बिजली विभाग मे लोगों की बढ़तीभीड़

कोरोना के समय में चाहे वह सब्जी के ठेले वाला हो या चाय के ठेले वाला हो या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला हो मंद पड़े व्यापार और खराब अर्थव्यवस्था के चलते दो वक्त की रोजी रोटी कमाने वाला या तो बिजली बिल भर ले या तो अपना पेट भर ले, बिजली विभाग में ऐसे लोगों की सुबह से ही भीड लगने लगती है, जो अपने बिल में राशि से असंतुष्ट होकर या तो सुधार करवाने आते है या फिर राशि को किश्तो में भरने के लिए आवेदन लगाने आते है। कई उपभोक्ताओं ने चर्चा में बताया कि, भारी भरकम बिल आने से आर्थिक बजट बिगड़ गया है। वहीं कई उपभोक्ताओं का कहना है, अधिकारी गुमराह कर घरों में खराब वायरिंग का हवाला देकर उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया जा रहा है, जबकि नए मकानों में भी सभी जगह एक साथ वायरिंग खराब बताना सभी की समस्या का हल नहीं है, अधिकारियों के इस प्रकार के बेतुके जवाब से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है।

इस सम्बंध में जब विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री आरएस बघेल से चर्चा की तो बताया, उपभोक्ताओं के बिलों को देखने के बाद ही स्थिति का पता चलेगा अगर बिल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन किया जाएगा तथा अधिक राशि के बिल भरने में कोई असमर्थ है तो उसकी किश्त की जा सकती है।

थाना प्रभारी को पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

आलोट कृषि विस्तारक अधिकारी द्वारा पत्रकार को जान से मारने की दी थी धमकी

माही की गूंज रतलाम, राघवेन्द्रसिंह डोडिया

रतलाम जिले के कालूखेड़ा में आलोट नगर स्थित अंबेडकर भवन में उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपने

कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले आलोट कृषि विस्तार अधिकारी को लताड़ लगाई गई थी, इससे पूर्व भी ताल और आलोट क्षेत्र में नकली कृषि दवाइयों को लेकर प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और साथ ही दुकानों पर मिलने वाली कृषि दवाइयां फसलों पर बेअसर हो रही है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारी के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके पश्चात एक न्यूज चौनल पर इस खबर को चलाया गया था, खबर के चलने के पश्चात एवं समीक्षा बैठक में पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के द्वारा सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पश्चात बौखलाए कृषि विस्तार अधिकारी धनपालसिंह तोमर द्वारा आलोट नगर निवासी एक न्यूज चैनल के संवाददाता राकेश मेवाड़ा को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि, तू मुझे जानता नहीं मैं नरेंद्र सिंह तोमर का रिश्तेदार हूं साथ ही पत्रकार के छपरा बिकवाने जैसे अप शब्दों का प्रयोग एवं अभद्रता करने को लेकर ग्रामीण पत्रकारो ने कालूखेड़ा थाना प्रभारी मधु राठौड़ को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

क्या भ्रष्ट अधिकारी इसी प्रकार पत्रकारों की लेखनी को दबाते रहेंगे, इसको लेकर कालूखेड़ा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमे उपस्थित सुनील जोशी, राहुल बैरागी, मुकेश नाथ कालूखेड़ा, राकेश मालवीय, प्रहलाद पंवार, जाफर मंसुरी, प्रभुलाल कुमावत आदि उपस्थित रहे।

योजनाबद्ध तरीके से पत्रकारों पर हो रहे हमले

झूठे प्रकरणों में उलझा कर चौथे स्तम्भ को दबाने का प्रयास, झूठा आरोप लगाने वाली महिलाए चुन्नु शर्मा के एसआर फेरो में करती है कार्य, जिला पत्रकार संघ ने पेटलावद थाने पर सौपा ज्ञापन

पेटलावद

गुरूवार को बामनिया के पत्रकार पर अज्ञात महिलाओं द्वारा पत्रकार पर छेडखानी जेसा घिनोना झूठा आरोप लगाकर पत्रकार की कलम को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। षडयंत्र पूर्वक दो महिलाओ को भेजकर पत्रकार पर महिलाओ से हमला करवाकर पत्रकार के विरूद्ध पेटलावद थाने में झूठा महिलाओ के साथ छेड़खानी का प्रकरण दर्ज करवाने का प्रयास किया। उक्त घटना का विरोध करते हुए जिला पत्रकार संघ झाबुआ के नेतृत्व में पुलिस थाना पेटलावद के थाना प्रभारी संजय रावत को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम से ज्ञापन सोप कर लगातार पत्रकारो के साथ हो रहे मामलो को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। जिला पत्रकार संघ ने पत्रकार पर हो रहे ऐसे षडयंत्रकारी हमले की निंदा करते हुए पत्रकार पर महिलाओ द्वारा हमले की निष्पक्ष जाँच कर हमले को अंजाम देकर पत्रकार को झूठे अपराध में फसाने का प्रयाश करने वालो को बेनकाब करने की मांग की है। जिसके बाद झूठी शिकायत कर्ता महिलाए एवं षडयंत्रकारी हरकत में आए और थाने पर महिला के साथ आए पूरूष ने समस्त पत्रकारो के सामने पुलिस को बताया कि, गलती से उक्त पत्रकार का नाम ले लिया गया था जिसका माफिनामा भी लिखकर महिलाओ द्वारा दिया गया वही उक्त पूरूष ने थाने में सार्वजनीक रूप से बताया वे सभी चुन्नु शर्मा के एसआर फेरो में कार्य करते है, उक्त खुलासे के बाद साफकहा जा सकता है कि, यह षडयंत्रकारी व महिलाओ का सहारा लेकर घिनोना कार्य किसने करवाया। जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष संजय भटेवरा ने मांग करते हुए बताया कि, पत्रकार निष्पक्ष होकर समाचार प्रकाशित करते हैं, जिससे कई बार अवैध धंदेबाज और भ्रष्ट लोग पत्रकारिता की कलम को दबाने के लिए ऐसे षडयंत्रकारी और घिनोना कृत्य कर जिसके लिए महिलाओं का सहारा लेकर झूठे प्रकरण दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे है और पुलिस प्रभाव और राजनीतिक दबाव में कई बार बिना जाँच पड़ताल के पत्रकार पर प्रकरण दर्ज कर लेती है, जिससे पत्रकारों को बिना अपराध के कानूनी प्रताड़ना से गुजर कर परेशान होना पड़ रहा है। पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री भटेवरा ने बताया कि, इस प्रकार से चौथे स्तम्भ को दबाने का जो प्रयास हो रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से उचित नही है। तहसील पत्रकार संघ के अध्यक्ष मोहन पडियार एवं समस्त पत्रकारों ने इस विषय को प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेकर पत्रकारों पर इस प्रकार से हो रहे हमलों की जाँच कर सत्यता का पता लगाकर ही कार्रवाई की मांग की है।

महिला के साथ थाने में आया उक्त युवक ने कहा महिला से गलती हुई है और हम सब चुन्नु शर्मा के यहाँ एसआर फेरो में करते है कार्य

बारिश ने बिगाड़ा भ्रष्टों का खेल, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जेसीबी से बना बचीखेड़ा का तालाब

उपयंत्री अहिरवार सहित सरपंच-सचिव और रोजगार सहायक को बचाने के लिए गोलमाल की जा रही जाँच

माही की गूंज, पेटलावद

बारिश के मौसम में हुई पहली ही बारिश ने भ्रष्टो का खेल बिगाड़ कर रख दिया, पेटलावद विकास खण्ड में मनरेगा योजना में मजदूरों को रोजगार देने के नाम पर हुए निर्माण कार्यो की पोल इस मोसम की पहली जोरदार बारिश में ही खुल गई। विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बचीखेड़ा में कुछ माह पूर्व ही बना जोसका वाली खाली का तालाब एक रात की बारिश में ही फूट गया है। तालाब की लागत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है, तालाब कुछ माह पूर्व ही बना था और मजदूरों की जगह जेसीबी से रातो-रात तालाब बना दिया गया था। मामले की शिकायत भी हुई, वीडियो भी वायरल हुए लेकिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक एक दूसरे पर आरोप लगाकर मामले में बचते रहे हैं। वही उपयंत्री अहिरवार को जेसीबी चलने की जानकारी निर्माण के दौरान रात में दे दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नही की गई, बाद में अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए जाँच में जेसीबी का कार्य किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ चलना बता कर शिकायत में सभी लापरवाही करने वालो को गोलमाल जॉच के साथ बचा लिया। पूरे मामले को गूंज ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, लेकिन जबाबदारो ने भ्रष्टो को जाँच में बचा लिया पर कहते है, झूठ के पैर नही होते और सच सामने आता ही है और घटिया निर्माण और मापदंडों के विपरीते हुए कार्य की पोल एक ही बारिश में खुल गई। भ्रष्टाचार के नाम पर खाना पूर्ति के लिए बना तालाब एक रात में ही फुट गया। मामले की शिकायत अमृतलाल भाभर, महेंद्र चंद्रावत और ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर की गई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नही हुई। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत अभी भी चल रही है, जाँच के दौरान लापरवाही बरतने वालो को बचाने के लिए बने झूठे पंचनामे तक को ग्रामीणों ने फाड़ दिया है। भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री सहित भ्रष्टाचारियो को जाँच में बचाने वाले जनपद सीईओ और मनरेगा एसडीओ और पटवारी पर कोई कार्रवाई करेगे या फिर अपना ईमान ओर कर्तव्यों को बेच कर फिर से इसमें भी लेन-देन कर भ्रष्टो को बचा लेगे?

गामडी ग्राम पंचायत में पुराना तालाब फूटा, कई किसानों की फसलें हुई बर्बाद

वही ग्राम पंचायत गामडी में भी बारिश के चलते करीब 5 वर्ष पुराना तालाब ग्राम गरबाडा स्कूल वाली नाकी का फूट गया। स्कूल वाली नाकी 10 लाख की लागत से करीब 5 वर्ष पहले बना था, इस वर्ष तेज बारिश के कारण तालाब में पानी अधिक भर जाने से तालाब पानी का दबाव सहन नहीं कर पाया और तालाब फूट गया, जिससे तालाब की पाल के नीचे किसानों के खेतों में पानी घुसने से किसानों के सोयाबीन, मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान हरिराम पिता बालू भुरिया और दशरथ भुरिया के खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई।

भगवान श्री गणेश मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित

माही की गूंज, पेटलावद

नगर के वार्ड क्रमांक 12 सुभाष मार्ग पर स्थित प्राचीनतम चमत्कारिक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर शुक्रवार-शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस आयोजन में वीर हनुमान मित्र मंडल आयोजन समिति के तत्वाधान में पंडित पंकज दवे, नितेश दवे आदि प्रकांड पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए भगवान गणेश की नवीन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसमें पूजन, हवन, भजन-कीर्तन के अलावा ध्वज चढ़ाने व शिखर भी स्थापित किया। कार्यक्रम में हवन व पूजन का लाभार्थी एडव्होकेट व पत्रकार मनोज पुरोहित एंव उनका परिवार रहा। दोपहर 12 बजे भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापना के पश्चात सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरे वार्ड वासियों ने महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त मंदिर वर्षों पुराना है जो कि जीर्ण-शीर्ण होने से सुभाष मार्ग के रहवासियों ने इसका पुनः निर्माण करते हुए नवीन स्वरूप दिया है जो कि आकर्षक एवं वैभवशाली रूप में दिखाई दे रहा है।

युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी इशिता का झाबुआ में एक दिवसीय दौरा आज

माही की गूंज, झाबुआ

भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस की प्रभारी इशिता सेढा झाबुआ के एक दिवसीय दौरे पर आज आ रही है, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया एवं उपाध्यक्ष विजय भगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि, इशिता दोपहर 2 बजे स्थानीय गोपाल कॉलोनी स्थित विधायक कार्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेगी। जिला युवा कांग्रेस ने अपने सभी पदाधिकारियों से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनकर अनिवार्य रूप से युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

गरीब आदिवासी के घर को दबंग अतिक्रमणकर्ताओं ने तीनों और से घेरा सीमांकन में निकली भूमि को राजस्व टीम ने दूसरी बार किए सीमांकन में किया गायब

न्याय के लिए लगाई गुहार तो बन गया परिवार का प्रकरण

माही की गूंज, पेटलावद, राकेश गेहलोत

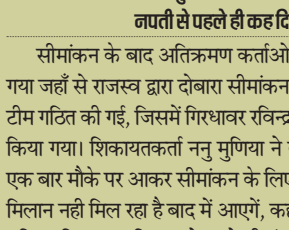

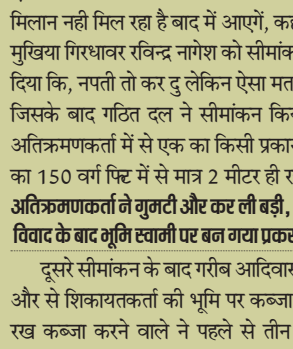

पहले सीमांकन में अतिक्रमण निकला पाया गया

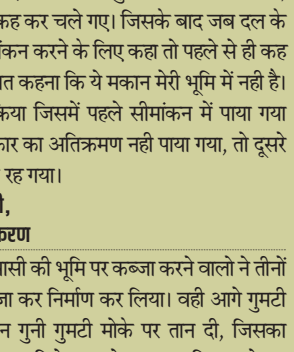

दूसरे सीमांकन में अतिक्रमण गायब हो गया

राजस्व विभाग की जादूगरी जग जाहिर है, यहाँ केवल वही भारी जिसकी जेब भारी है। पेटलावद राजस्व न्यायालय में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां गरीब आदिवासी स्वयं के मालिकी की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जब न्याय के लिए गरीब राजस्व विभाग के शरण मे पहुँचा तो न्याय तो नही मिला उल्टा विपक्षी इतने भारी पड़ गए कि, पूरे परिवार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो गया। मामला पेटलावद राजस्व का है, जहा ग्राम बनी में ननु, नन्दू और वालीबाई के नाम से राजस्व रिकार्ड में सर्वे नम्बर 301 रकबा 5 आरा की भूमि दर्ज है, चुकी भूमि बनी-राजगढ़ रोड स्थित है, इसलिए कीमत भी अधिक है। उक्त भूमि के आगे बाबू पिता भेरु द्वारा गुमटी रख दी जिसको अपने आगे से हटाने के लिए ननु मुणिया ने सीमांकन का विधिवत आवेंदन तहसील न्यायालय पेटलावद में प्रस्तुत किया 25 फरवरी को राजस्व टीम द्वारा गिरदावर और पटवारी की उपस्थिति में राजस्व टीम के साथ सीमांकन किया गया, जिसमें नपती के बाद सर्वे नम्बर 305 पुरषोत्तम प्रेमचंद पाटीदार और रामनारायण पिता धन्नालाल पाटीदार 150-150 वर्ग फीट का अतिक्रमण पाया गया, साथ ही बाबू पिता भेरू की गुमटी भी आधी सरकारी भूमि और आधी शिकायतकर्ता की भूमि में पाई गई, लेकिन सीमांकन की रिपोर्ट में उल्लेख नही किया गया।

दोबारा हुए सीमांकन में अतिक्रमण हुआ गायब, नपती से पहले ही कह दिया मकान नही आएगा

सीमांकन के बाद अतिक्रमण कर्ताओ द्वारा दोबारा सीमांकन हेतु आवेंदन दिया गया जहाँ से राजस्व द्वारा दोबारा सीमांकन किया गया, सीमांकन के आदेश के बाद टीम गठित की गई, जिसमें गिरधावर रविन्द्र नागेश के द्वारा मोके पर जाकर सीमांकन किया गया। शिकायतकर्ता ननु मुणिया ने बताया कि, राजस्व द्वारा गठित टीम द्वारा एक बार मौके पर आकर सीमांकन के लिए नपती करना शुरू कर दी और कहा कि, मिलान नही मिल रहा है बाद में आएगें, कह कर चले गए। जिसके बाद जब दल के मुखिया गिरधावर रविन्द्र नागेश को सीमांकन करने के लिए कहा तो पहले से ही कह दिया कि, नपती तो कर दु लेकिन ऐसा मत कहना कि ये मकान मेरी भूमि में नही है। जिसके बाद गठित दल ने सीमांकन किया जिसमें पहले सीमांकन में पाया गया अतिक्रमणकर्ता में से एक का किसी प्रकार का अतिक्रमण नही पाया गया, तो दूसरे का 150 वर्ग फिट में से मात्र 2 मीटर ही रह गया।

अतिक्रमणकर्ता ने गुमटी और कर ली बड़ी, विवाद के बाद भूमि स्वामी पर बन गया प्रकरण

दूसरे सीमांकन के बाद गरीब आदिवासी की भूमि पर कब्जा करने वालो ने तीनों और से शिकायतकर्ता की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लिया। वही आगे गुमटी रख कब्जा करने वाले ने पहले से तीन गुनी गुमटी मोके पर तान दी, जिसका शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध करने पर रायपुरिया थाने पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, जिसमें शिकायतकर्ता के परिवार के 8 लोगो के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जबकि विवाद वाले दिन घर के कुछ सदस्य तहसील न्यायालय में तारीख पर मौजूद थे, जिसके बाद भी प्रकरण में मोके पर नही होने के मौजूद लोगो को नामजद कर दिया गया, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा की गई रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई नही की गई। जबकि एक अन्य अतिक्रमणकर्ता द्वारा निर्माण को लेकर विवाद कर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट भी की गई, जिनके विरुद्ध मारपीट का प्रकरण दर्ज किया।

अपील की पर सुनने वाला कोई नही

दूसरी बार हुए सीमांकन के बाद पीड़ित परिवार ने राजस्व न्यायालय में फिर से गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई नही है। वर्तमान में गरीब आदिवासी की भूमि पर बना स्वयं का मकान अधूरा पड़ा है और तीनों और से अतिक्रमण से घिरा हुआ है। राजस्व विभाग में जिसकी लाठी उसकी भैस की कहावत चरितार्थ होती नजर आरही है जहाँ प्रभावी और बड़े लोग किसी भी गरीब को दबा कर उसकी जमीन राजस्व विभाग के साथ मिलकर आसानी से हतिया सकते हैं।

कारस्तानी : जनपद पंचायत पेटलावद के फर्जी प्रस्ताव पर हुई बाबू अटकान की बहन की नियुक्ति

एक ही तारिख, एक ही आदेश क्रमांक में दो स्थान पर कर दी नियुक्ति, जाँच में मामले को दबाया

6 जनवरी 2011 को जारी सहायक आयुक्त का आदेश 354 जिसमे बाबू की बहन को कन्या उमावि पेटलावद से कन्या उमावि बामनिया कार्य करने की अनुमति दी।

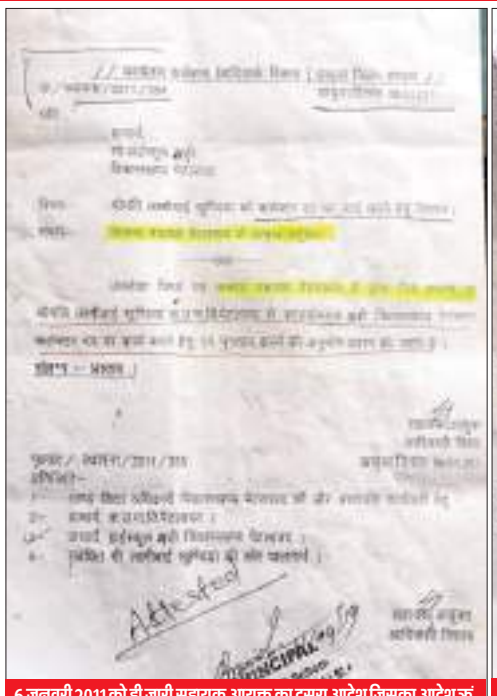

6 जनवरी 2011 को ही जारी सहायक आयुक्त का दूसरा आदेश जिसका आदेश क्रं. 354 ओर दिनांक एक ही है जिसमे बाबू की बहन को कन्या उमावि पेटलावद से शा.हाईस्कूल गढ़ी पेटलावद में कार्य करने की अनुमति दी।

सूचना अधिकारी में जनपत पेटलावद से प्राप्त जानकारी जिसमें बाबू की बहन लक्ष्मी खुंडिया के लिए कोई प्रस्ताव नही होने की जानकारी दी गई।

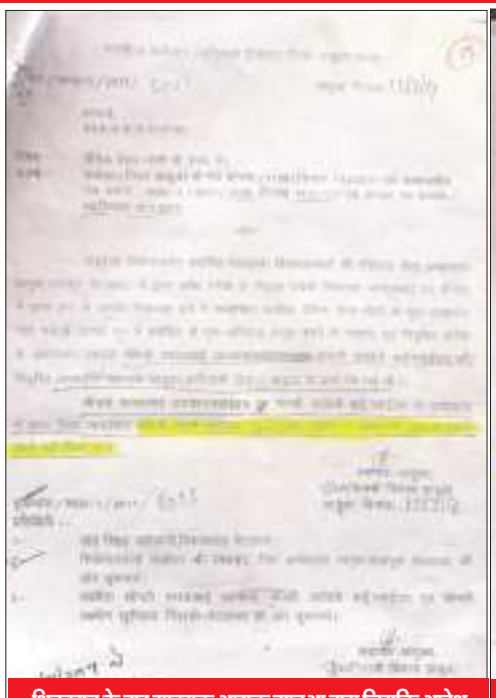

शिकायत के बाद साहयक आयुक्त झाबुआ द्वारा नियुक्ति आदेश संदेहस्पद होने पर कार्य नही लेने के आदेश 12 जुलाई 2017

भोपाल के आदेशो को ताक में रख 17 जनवारी 2018 को सहायक आयुक्त झाबुआ द्वारा मिलीभगत कर फिर से नियुक्ति कर दी गई।

माही की गूंज झाबुआ, संजय भेटवरा

आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत पेटलावद विकास खंड में हुए नियुक्ति घोटाला माही की गूंज में परत दर परत खुलने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पेटलावद बीईओ कार्यालय में पदस्थ बाबू रामचंद्र अटकान के परिवार के सदस्यों की नियुक्ति पर पहली बार पुरा खुलासा गूंज के माध्यम से हो रहा हैं, इससे पहले पूरा मामला शिकायत के बाद विभागीय जाँच ओर जाँच के नाम पर हुए लेंन-देन के साथ दब चुका था, अपनी गर्दन बचाने के लिए अधिकारियों ने अपने आपको पाक साफ बताकर बड़े अधिकारियों को गुमराह कर या साठ-गाठ कर अब तक अपनी गर्दन बचा रखी है। भर्ती प्रक्रिया की अनियमित्ता के बाद जाँच में भारी अनियमित्ता के चलते मामले में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नही हो सकी जिससे उपकृत हुए जिम्मेदार अधिकारी बाबू के साथ मिलकर एक के बाद एक फर्जी और अवैध नियुक्ति प्रदेश स्तर के आदेशों को हवा में उड़ाकर ऐसे करते गए मानो जैसे फर्जी नियुक्ति का कोई लाइसेंस मिल गया हो।

जनपद के फर्जी प्रस्ताव पर बाबू की बहन की लगी नोकरी, अधिकारीयों की जानकारी में आने के बाद भी दबा दिया पूरा मामला आखिर क्यो ?

अपनी कारस्तानियो के साथ कारस्तानियो का मसिहा बन चुका बाबू रामचंद्र अटकान ने अपने भाई व पत्नी की तरह खुद की बहन की भी आदिवासी विकास विभाग में नोकरी दिलवा दी, बाबू ने अपनी बहन को खुद की पत्नी के साथ वर्ष 1991 में अंशकालीन स्वीपर पद पर कन्या उमावि पेटलावद में 17 जनवरी 1991 को पदस्थ करवा दिया था। उक्त नियुक्ति में भी कहानी वही है पत्नी की तरह बहन को भी स्थाईकर्मी बनाने के लिए कलेक्टर दर पर नियुक्ति होना जरूरी है, बस इसी के लिए एक फर्जी खेल वर्ष 2011 में ओर रचा गया जब जनपत पंचायत के एक प्रस्ताव को आधार बनाकर 6 जनवरी 2011 को आदेश क्रमांक 354 के माध्यम से बाबू की बहन को कन्या उमावि पेटलावद से, कन्या उमावि बामनिया में कलेक्टर दर पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त आदेश में भी पहले की तरह किसी पद का कोई उल्लेख नही किया गया, अधिकारी के आदेश के बाद भी कन्या उमावि बामनिया प्राचार्य ने विभाग में अपनी कारस्तानी व अपना प्रभाव दिखाने वाले बाबू अटकान की बहन को जॉइन करने से मना कर दिया, चुकी इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया था। अटकान की बहन को फर्जी रूप से बामनिया में पदस्थ करवाने के लिए बामनिया कन्या प्राचार्य पर दबाव डालने की बजाए दूसरे फर्जीवाड़े की व्यवस्था की गई। पासा उल्टा पड़ने के बाद बाबू अटकान ओर प्राचार्य ने सहायक आयुक्त से ऐसी सेटिंग बिठाइ कि, इसी आदेश क्रमांक 354 पर उसी दिनांक में नया आदेश जारी किया गया, जिसमें बाबू की बहन को कन्या हाई स्कूल गढ़ी पेटलावद में कार्य करने की अनुमति दी गई। दोनों ही आदेशो में पद का कोई उल्लेख नही किया गया, जिसके बाद भी प्राचार्य योगेन्द्र प्रसाद और बाबू रामचंद्र अटकान ने महिला को भृत्य बताकर वेतन का लगातार भुगतान किया। मामले की शिकायत रमेश धानक द्वारा उच्चधिकारियों को की गई, जिसमें नियुक्ति को पूर्ण रूप से फर्जी बताकर नियुक्ति को फर्जी घोषित करने वाले दस्तावेज भी सलंग्न किए। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता रमेश धानक को जनपत पंचायत पेटलावद से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई जानकारी में ये स्पष्ट लिखा गया कि, श्रीमती लक्ष्मी खुंडिया को कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु जनपत पंचायत पेटलावद द्वारा सत्र 2010-2011 में कोई प्रस्ताव नही किया, इतना ही नही पेटलावद नगर में नियुक्ति हेतू जनपत पंचायत का प्रस्ताव मान्य नही होता, उसके लिए शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी नगर परिषद होती हैं, फिर भी फर्जी जनपद के प्रस्ताव के आधार पर सहायक आयुक्त द्वारा लेंन-देन के साथ प्रभाव में आकर फर्जी नियुक्ति आदेश एक बार नही बल्कि दो बार एक ही आदेश क्रमांक ओर एक ही दिनांक में जारी कर दिया आखिर कैसे ?

शिकायत होने पर रोका गया था वेतन, भोपाल से जारी आदेश को ताक में रख अधिकारी ने फिर करा बहाल

मामले की शिकायत रमेश धानक द्वारा पर्याप्त दस्तावेजो के साथ की गई, प्रथम जाँच में उक्त नियुक्ति को संदेहास्पद मान कर महिला (बाबू की बहन) से कार्य नही लिया जावे का आदेश जारी सहायक आयुक्त झाबुआ द्वारा किया गया। मार्च 2017 में कार्य बंद करने के बाद मामले में अधिकारियों से बाबू ने पटरी बिठा ली, जिसके बाद सहायक आयुक्त झाबुआ द्वारा आदेश क्रमांक 523/17 जनवरी 2018 को बाबू की बहन को भृत्य के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में मावि गढ़ी पेटलावद में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जबकि जांच चलने के उपरांत नियुक्ति नहीं होना थी। जैसे ही सहायक आयुक्त मैडम का ट्रांसफर हुआ वैसे ही बाबू ने अपनी सेटिंग जमाकर पुनः नियुक्ति करवा ली और मावि गड़ी पेटलावद में पद रिक्त नहीं होने के बाद भी नियुक्ति की गई।

आदिवासी विकास भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 10866/9 मई 2017 को जारी किया गया आदेश, जिसमे स्पष्ट किया गया कि, विभाग में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार की चतुर्थ श्रेणी, अंशकालीन, स्वीपर, भृत्य, चौकीदार, वाटरमैन की भर्ती नही की जाए। भोपाल से जारी आदेश जो ताक में रख कर अपने कारनामे छुपाने के लिए बाबू की बहन की नियुक्ति सहायक आयुक्त द्वारा कर काम पर रख लिया गया। रामचंद्र अटकान सहायक ग्रेड-2 बाबू का प्रभाव इतना हैं कि कलेक्टर और सहायक आयुक्त ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी साठ-गाठ के साथ अपनी कार्य की इतिश्री कर रहे है।

मौत, जगह और वक्त नही देखती, दर्शन के लिए गए और भगवान को प्यारे हो गए मांगू भगत

माही की गूंज, बनी

आज सुबह गांव के मांगू देवा भाभर जो गाव में मांगू भगत के नाम से ही जाने जाते हैं, ग्राम बनी में अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित हनुमान जी मंदिर पर अगरबत्ती लगाकर दर्शन कर ही रहे थे कि, अचानक हनुमान जी के सामने गिर गए और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली, यह खबर सुनकर गांव के सभी लोग आश्चर्य चकित हो गए और मांगू भगत की मौत के बारे में कहने लगे की भगत की करनी बहुत अच्छी थी और उन्होंने अच्छी मौत प्राप्त की, वैसे भी मांगू भगत के नाम से जाने वाले सीधे-सादे सरल व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। जैसे ही उनके निधन की खबर मिली पूरा परिवार शोक में डूब गया।

बामनिया को मिलेगी नए मार्केट की सौगात, नवीन पंचायत भवन, शुलभ शौचालय और पत्रकार संघ कार्यालय

माही की गूंज बामनिया, गौरव भंडारी

अन्य बड़ी पंचायतो के मुकाबले बामनिया ग्राम पंचायत में जो विकास होना था उसमे काफी पीछे रह गई है, स्थानीय राजनीति में चल रही टांग खींचो प्रतियोगिता के कारण कोई बड़ी योजना पंचायत में विगत 3 वर्षो में नही आ सकी हैं। वही ग्राम पंचायत भवन के पास रिक्त पड़ी शासकीय भूमि पर वर्षो से मार्केट बनाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अब तक उसे जमीन पर नही उतारा जा सका हैं, लेकिन अब लगता हैं कि, वर्षो का यह इंतजार अब समाप्त होने वाला है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन के पास एक मार्केट बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका भुमिपूजन भी हो चुका है, जल्द ही एक भव्य मार्केट जिसमे लगभग 30 दुकाने बनना प्रस्तावित हैं, बड़ी संख्या में बनने वाली इन दुकानों से कई बेरोजगारो को स्थाई रोजगार की उम्मीद जगी हैं। ग्राम पंचायत के अनुसार पंचायत भवन के पास खाली पड़ी

भूमि पर 30 दुकानों के साथ नवीन पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाना है, साथ ही ग्राम पंचायत में आने वालों ग्रामवासियों ओर दुकानदारो की सुविधा को देखते हुए शुलभ शौचालय का निर्माण किया जाएगा। फ्लिहाल ग्राम पंचायत के इस निर्णय से नगर को नई सौगात जल्द मिलने की उम्मीद तो जगी हैं, लेकिन जिस तरह ग्राम की राजनीति चल रही है यहाँ विकास के नाम पर राजनीतिक विरोधियों में कभी एकता नही दिखी है, न ही कुर्सी पर बैठे जबाबदारो ने कोई इस दिशा में कभी पहल की, जिसका खामियाजा वर्षो से ग्रॉम की आम जनता भुगत रही हैं।

पत्रकार संघ भवन को लेकर असमंज, सरपंच ने कहा दूसरी मंजिल पर बनेगा पत्रकार हाल

ग्राम पंचायत परिसर में जहां दुकाने बन रही है, वहा पूर्व से आबंटित पत्रकार भवन भी है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जा रहे मार्केट के नक्शे में पत्रकार भवन का कोई उल्लेख नही है, जिससे निर्माण के दौरान पत्रकार संघ विरोध दर्ज कर सकता है। मामले में ग्राम पंचायत सरपंच रामकन्या मखोड़ का कहना है कि, मार्केट के ऊपर पत्रकार संघ भवन के लिए एक हाल बना कर दिया जाएगा, हालांकि स्थानीय पत्रकारों से ग्राम पंचायत की अब तक कोई चर्चा नही हुई है न ही लिखित में या रिकॉर्ड पर पत्रकार भवन का कोई उल्लेख हैं और न ही स्थानीय पत्रकारो को इसकी कोई जानकारी है, लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा संघ हेतु हाल बनवाने की बात सामने आने से मामले का निकाल हो सकता है।

कोरोना काल के साथ अब अतिवृष्टि के कारण किसान हुआ बेहाल

माही की गूंज, खवासा

कोराना काल में हर व्यक्ति का हाल बेहाल है, वही किसानों की किस्मत दोहरी मार को झेलने के लिए मजबूर हो गए है। इस वर्ष बारिश का मौसम शुरू होने के बाद छुट-मूट बरसात हो रही थी, वही किसानों की क्षेत्र में होने वाली मुख्य एवं नकदी फसलों में अज्ञात वायरस आ गया था, तो वही इल्ली व सफेद मक्खी, मकड़ी आदि ने फसलों को कई हद तक खराब कर दिया था। तो वही अच्छी बारिश का इंतजार इस वर्ष कर रहे थे की शुक्रवार रात से हुई दो दिनों तक ऐसी बारिश हुई की फसलों को बर्बाद ही कर दिया और किसानों की कमर पूरी तरह से टूट सी गई है।

क्षेत्र में टमाटर, सोयाबीन, मक्का, मिर्ची की मुख्य फसल होती है। बुधवार को किसानों ने सूचनार्थ पुलिस चौकी खवासा में खराब हुई फसल के संबंध

में लिखित प्रतिवेदन देकर बताया कि, क्षेत्र में दो दिन में ही हुई अतिवृष्टि के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है एवं खराब सभी फसलों का राजस्व कृषि एवं उद्यानिकी विभाग वीडियोग्राफी करवा कर मुआवजा वितरण की त्वरित व्यवस्था करवाएं। साथ ही किसानों ने पुलिस चौकी में सूचित किया कि, गुरुवार को टप्पा तहसील खवासा में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर मुआवजा एवं किसानों के हक के लिए ज्ञापन सौंपेंगे।

चौकी पर इस दौरान एक फित्तरती युवक सुरेश भगत ने मीडियाकर्मी सूचना मिलते ही किसानों के हक की बात को प्रकाशित करने के लिए समाचार संकलन हेतु पहुंचा तो फित्तरती युवक ने विपरीत दिशा में बात कर कहने लगा, मीडिया का कोई काम यहां नहीं है यह मीडियाकर्मी यहां अब क्यों आया? उक्त बात मीडिया कर्मी ने अपने वरिष्ठ पत्रकार को बताई जब इस संबंध में फित्तरती सुरेश भगत से बात की कि, किस आशय के साथ आपने हमारे मीडियाकर्मी को यह बात कही तो फित्तरती युवक झूठ बोल रहा है यह मैंने नहीं कहा व मोबाइल अन्य वरिष्ठ किसानों को दे दिया। सभी के समक्ष कही फित्तरत युवक द्वारा पत्रकारों को कही बात सभी किसानों को गलत लगी है जिस पर वरिष्ठ किसान ने उक्त युवक की हरकत को छिछोरी हरकत बता कर क्षमा मांगी।

अपनी सेवाभावी कर्तव्य शैली के अनुरूप श्री प्रबल हमेशा रहेंगे याद

माही की गूंज, झाबुआ/मेघनगर

जिले से स्थानांतरित कलेक्टर प्रबल सिपाहा की विदाई पर मेघनगर रोटरी क्लब द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर कलेक्टर प्रबल सिपाह को सम्मानित किया। रोटरी क्लब के भरत मिस्त्री ने बताया कि, अपने बीच से एक ऊर्जावान एवं सरल, सहज स्वभाव, मिलनसार, गरीब हितैषी तथा अधिकारी, कर्मचारियों को एक परिवार का सदस्य मानते हुए जिले के चहुंमुखी विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने व कोविड-19 की रोकथाम में विशेष योगदान के साथ कार्य करने वाले कलेक्टर सिपाहा का सम्मान करते हुए रोटरी क्लब द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर सिपाहा ने कहा कि, यह शासन की प्रक्रिया है, हम सबका स्थानांतरण होता रहता है, झाबुआ बहुत सुंदर जिला है, यहां विकास की अभी बहुत आवश्यकता है, यहां की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं

स्थानतरित कलेक्टर प्रबल सिपाहा को रोटरी क्लब ने दी विदाई

अधिकारियों के सहयोग से मॉडल रोड, पेयजल, खाद की रैक, हैण्डपम्पों का उत्खनन, आजीविका मिशन, स्वसहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सक्रिय योगदान रहा। वहीं कोविड-19 कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जिस तरह से अधिकारी, कर्मचारियों के साथ कई समाज सेवी संगठन के साथ रोटरी क्लब अपना ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया वह प्रशंसनीय है। आप सभी निष्ठापूर्वक आगे भी इसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिले के विकास में अपना योगदान देवें। इस अवसर पर रोटरी क्लब अपना के अध्यक्ष पंकज राका, सचिव राजेश भंडारी, रोटेरियन भरत मिस्त्री, मांगीलाल नायक, अजय रामावत, निलेश भानपुरिया, आर.सी.सी क्लब से श्रीमती शर्मा, रोट्रेक्ट क्लब से तेजस जैन उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422